A Daily News Magazine
भोपाल
बुधवार, 16 अप्रैल, 2025

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 216, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

बीजद: पार्टी नेता नवीन पटनायक को भीतर से मिल रही चुनौती

मौसमी दास गुप्ता

बीजू जनता दल (बीजद) के प्रमुख नवीन पटनायक का पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता द्वारा खुलकर विरोध दुर्लभ बात है। पिछले सप्ताह, 13 बीजद नेताओं ने पार्टी मुख्यालय शंख भवन के बजाय भुवनेश्वर के एक होटल में चर्चा के लिए मुलाकात की। नवीन पटनायक द्वारा होटल में हुई बैठक की आलोचना करने के बाद, बैठक में शामिल हुए तीन बार के बीजद विधायक नृसिंह साहू ने संवाददाताओं से कहा, 'कोई भी यह तय नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति दूसरे से कहां मिलेगा।'

बीजद जैसी क्षेत्रीय पार्टी के 27 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। 2024 के राज्य और लोकसभा चुनावों में पार्टी की अपमानजनक हार के बाद, यह बीजद संकट को उजागर करने वाली नवीनतम झड़प है। पहली बार बीजद नेता पटनायक पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। बीजद नेता नरसिंह साहू ने होटल में बैठक से छह दिन पहले वरिष्ठ नेताओं ने पटनायक से मुलाकात की थी और वक्फ विधेयक पर पार्टी के यू-टर्न के बारे में चिंता व्यक्त की थी, जिसे राज्यसभा ने 4 अप्रैल को पारित किया था।

'24 साल तक, जब नवीन पटनायक सत्ता में थे, किसी भी नेता ने उनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब, वे पार्टी प्रमुख से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं-चाहे वह वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 पर हो या उनके भरोसेमंद सहयोगी वी.के. पांडियन की भूमिका पर हो। 2000 बैच के आईएएस अधिकारी पांडियन दो दशकों से अधिक समय तक पटनायक के निजी सचिव रहे। उन्होंने नवंबर 2023 में बीजद में शामिल होने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, लेकिन 2024 के चुनाव में पार्टी के हारने के बाद उन्होंने राजनीति से हटने की घोषणा की। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजद ने 147 सीटों में से 51 सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी ने 78 सीटें जीतीं और मोहन चरण माझी के नेतृत्व में सरकार बनाई। चुनाव के बाद तीन निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे इसकी संख्या 81 हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की शर्मनाक हार और भी भयावह रही। ओडिशा की 21 सीटों में से वह एक भी नहीं जीत पाई। बीजेपी ने 20 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को एक सीट मिली।'

राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंतराय, पूर्व मंत्री प्रताप जेना और छह बार विधायक रहे प्रफुल्ल सामल और बद्री पात्रा जैसे वरिष्ठ नेताओं ने वक्फ बिल पर बीजेडी के ढुलमुल रवैये की खुलकर आलोचना की है, जिससे बीजेडी का संकट और बढ़ गया है। पार्टी प्रमुख नवीन पटनायक ने तीन बार बिल का विरोध किया था, लेकिन जब पिछले महीने राज्यसभा में इस पर मतदान हुआ, तो बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने सोशल मीडिया पर पार्टी सांसदों से वोटिंग के दौरान 'अपने विवेक का इस्तेमाल' करने का आग्रह किया। बिल के पारित होने के बाद, बीजेडी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पटनायक से उनके आवास पर कई बार मुलाकात की और आखिरी समय में रुख में आए बदलाव पर चिंता जताई।

इस मुद्दे पर पटनायक से मिलने वाले बीजद के एक नेता ने बताया कि नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा- न केवल वक्फ बिल पर बल्कि पार्टी लाइन पर भी- क्योंकि ओडिशा में 24 साल के शासन के बाद बीजद की विपक्ष की स्थिति पर धूल जम गई है। बीजद संकट पर चर्चा करते हुए, एक नेता ने कहा, 'आंतरिक रूप से, हममें से कई लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है- बीजद का क्या मतलब है? नेता और पार्टी कार्यकर्ता दोनों ही भ्रमित हैं. क्या हम भाजपा के साथ हैं, या हम उससे लड़ रहे हैं? क्या हम भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बनाए रखने की अपनी नीति जारी रखेंगे?'

बीजद के संगठनात्मक चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं, इसलिए संभावना है कि नवीन पटनायक को पांच दिनों में यानी 19 अप्रैल को फिर से पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। इस पृष्ठभूमि में, पार्टी के भीतर स्पष्ट दिशा के लिए आवाज तेज हो गई है। बीजेडी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि पार्टी अब अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना कर रही है- विपक्षी पार्टी के रूप में राजनीतिक स्थान को कैसे संभालना है। बीजेडी के वरिष्ठ नेता और पटनायक सरकार में पूर्व मंत्री अशोक पांडा ने कहा अब समय आ गया है कि पार्टी अपनी राजनीतिक विचारधारा पर स्पष्ट बयान दे और अन्य राजनीतिक दलों के साथ अपना रुख स्पष्ट करे।

'बीजेडी प्रवक्ता लेनिन मोहंती ने बीजेडी संकट से इनकार किया और कहा कि वरिष्ठ नेताओं ने नवीन पटनायक से सवाल पूछे हैं। पार्टी के वक्फ बिल पर उलटफेर पर मोहंती ने कहा कि बिल के कानून बनने के बाद अल्पसंख्यक नेताओं से मिलने वाले 'नवीन बाबू' देश के एकमात्र नेता हैं। उन्होंने फिर से जोर दिया है कि हम अपने धर्मनिरपेक्ष आदर्शों पर चलते रहेंगे।' उन्होंने कहा कि बीजेडी की केवल मुद्दों का समर्थन करने की नीति जारी रहेगी, पार्टियों का नहीं।

पिछले साल ओडिशा विधानसभा और लोकसभा चुनावों में हार के तुरंत बाद, बीजेडी ने यह पता लगाने के लिए कि कैडर का विश्वास कैसे बहाल किया जाए और पार्टी को फिर से संगठित किया जाए, अपने 17 वरिष्ठ नेताओं की एक सलाहकार समिति का गठन किया। पार्टी के तीन वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, बीजेडी संकट से निपटने के लिए समिति ने सुधारों का छह सूत्री चार्टर तैयार किया। सिफारिशों में से एक यह है कि पार्टी को पार्टी अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक संसदीय बोर्ड का गठन करना चाहिए। संसदीय बोर्ड को सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने चाहिए। पार्टी के पास एक राजनीतिक सलाहकार समिति थी, लेकिन 2003-04 में इसे भंग कर दिया गया। तब से, पटनायक अकेले ही सभी निर्णय लेते हैं। चूंकि संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं, इसलिए हमने संसदीय बोर्ड के गठन की सिफारिश की है। तीनों नेताओं ने बताया कि 17 सदस्यीय सलाहकार समिति ने लगभग चार महीने पहले नवीन पटनायक को चार्टर दिया था, लेकिन तब से उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। जून में विपक्ष की स्थिति में बीजद का एक साल पूरा होने वाला है, लेकिन नवीन पटनायक के सहयोगी वी.के. पांडियन की भूमिका नेताओं को परेशान कर रही है। हार के बाद पांडियन ने अपने इस्तीफे की घोषणा की, लेकिन वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया कि वह पार्टी के मामलों में हस्तक्षेप करना जारी रखे हुए हैं।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

तुम कहाँ से आए हो कवि
किन रस्तों की धूल है तुम्हारे पाँवों में
किन कुओं का जल पिया है तुमने
किन पेड़ों के नीचे सुस्ताए हो
किन जगहों पर रात्रियाँ बिताई हैं
किन घरों का अन्न खाया है
किनसे भर भर बाथ मिले हो
किनको गले लगाया है
किन स्त्रियों ने पाला पोसा प्यार किया तुमको
किन बच्चों को लाड़ लड़ाया तुमने
किनके दुख में डूब डूब तुम भीग गए
किनके सुख में खिल खिल आए हो
सबकी गंध बसी है कविवर कविताओं में
जिनसे वे जानी पहचानी जाती हैं
गंध झूठ की भी होती है लेकिन कवि जी
रह रह जिसका भभका उठता है कविताओं से।

– विनोद पदरज

छह साल में जो नहीं हुआ वो हो गया...

सेंसेक्स बना रॉकेट, महंगाई घटी खाने-पीने की चीजों के दाम में कमी

मार्च में महंगाई 6 साल के निचले स्तर पर, 3.34 प्रतिशत रही रिटेल इन्फ्लेशन

नई दिल्ली (एजेंसी)। खुदरा महंगाई मार्च में घटकर छह साल में सबसे कम हो गई है। ये आंकड़े शेयर बाजार बंद होने के बाद जारी हुए। मंगलवार को बाजार में बंपर तेजी देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर टैरिफ में छूट की घोषणा से सेंसेक्स 1,578 अंक ऊपर गया। मार्च में थोक महंगाई भी घटी है। सब्जियों और प्रोटीन वाली चीजों के दाम कम होने से खुदरा महंगाई दर मार्च में घटकर 3.34 फीसदी रह गई। यह पिछले छह सालों में सबसे कम है। इससे पहले अगस्त 2019 में यह दर 3.28 फीसदी थी। भारतीय रिजर्व बैंक इस महंगाई दर को ध्यान में रखकर ही अपनी नीतियां बनाता है। केंद्रीय बैंक ने पिछले हफ्ते रेपो रेट को 0.25 फीसदी घटाकर 6 फीसदी कर दिया था।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा महंगाई फरवरी में 3.61 फीसदी थी। पिछले साल मार्च में यह 4.85 फीसदी थी। इस बार मार्च में यह और भी कम हो गई है। खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर मार्च में 2.69 फीसदी रही। फरवरी में यह 3.75 फीसदी थी। पिछले साल मार्च में यह 8.52 फीसदी थी। इसका मतलब है कि खाने-पीने की चीजें अब पहले से सस्ती हो रही हैं।

शेयर बाजार ने लगाई दौड़

उधर, मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स 1,578 अंक ऊपर गया। एनएसई निफ्टी 500 अंक फायदे में रहा। बीएसई सेंसेक्स 1,577.63 अंक यानी 2.10 फीसदी बढ़कर 76,734.89 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह एक समय 1,750.37 अंक तक चढ़ गया था।

- **2025-26 में खुदरा महंगाई 4 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान-** आरबीआई का कहना है कि आने वाले वित्त वर्ष 2025-26 में खुदरा महंगाई दर 4 फीसदी के आसपास रहेगी। उनका अनुमान है कि पहली तिमाही में यह 3.6 फीसदी, दूसरी तिमाही में 3.9 फीसदी, तीसरी तिमाही में 3.8 फीसदी और चौथी तिमाही में 4.4 फीसदी रहेगी। आरबीआई का यह भी कहना है कि महंगाई दर ऊपर या नीचे भी जा सकती है। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई दर भी मार्च में घटकर 2.05 फीसदी पर आ गई है।

ये कैसे मां-बाप?

पहले बच्चों को जहर दिया फिर ब्लेड से गला रेता

जोधपुर (एजेंसी)। फलौदी जिले के लोहावट थाना क्षेत्र के कोलू पाबूजी गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है। पति-पत्नी के बीच विवाद ने तीन बच्चों की जिंदगी छीन ली। माता-पिता के अपनी दो बेटियों समेत तीन बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी। बच्चों की हत्या के बाद माता-पिता ने जान देने की कोशिश की लेकिन बच गए। फिलहाल दोनों का फलौदी अस्पताल में इलाज चल रहा है। फलौदी एसपी पूजा अवाना ने बताया कि कोलू पाबूजी निवासी 35 वर्षीय शिवलाल मेघवाल के घर बच्चों की गला रेत कर हत्या की जानकारी मिली। पुलिस पहुंची तो तीन बच्चों के गले रेते शव मिले। शिवलाल और उसकी पत्नी जतनो भी अचेत मिले। एसपी अवाना ने बताया कि पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। रात को उन्होंने पहले बच्चों को जहर दिया। उसके बाद उनकी हत्या कर दी। इसके बाद शिवलाल व उसकी पत्नी ने खुदकुशी करने का प्रयास किया।

राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी

- तमिलनाडु से ई-मेल आया, लिखा- बढ़ा लो मंदिर की सुरक्षा; सर्च ऑपरेशन जारी

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 14 अप्रैल (सोमवार) की रात राम जन्मभूमि ट्रस्ट को एक ई-मेल आया था। इसमें लिखा है- बढ़ा लो मंदिर की सुरक्षा। ट्रस्ट के अकाउंट अफसर महेश कुमार ने मंगलवार को पुलिस की साइबर सेल में केस दर्ज कराया है। धमकी मिलने के बाद जन्मभूमि परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली को एक्टिव किया गया है। पुलिस ने मंदिर के पास सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं, बाराबंकी, चंदौली और अलीगढ़ समेत कई जिलों के जिलाधिकारियों को भी धमकी भरा ई-मेल आया है। इसमें डीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये सभी मेल तमिलनाडु से भेजे गए हैं।

राम मंदिर, अयोध्या

तमिलनाडु की साइबर सेल को भी एक्टिव किया गया

संदिग्ध ई-मेल की सूचना मिलते ही तमिलनाडु की साइबर सेल को भी अलर्ट कर दिया गया है। जिससे ई-मेल भेजे जाने की सटीक लोकेशन और इसके पीछे मौजूद शातिर की पहचान की जा सके। बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से कई बार धमकी मिल चुकी है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू भी कई बार धमकी दे चुका है। अयोध्या पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह से बचें।

अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

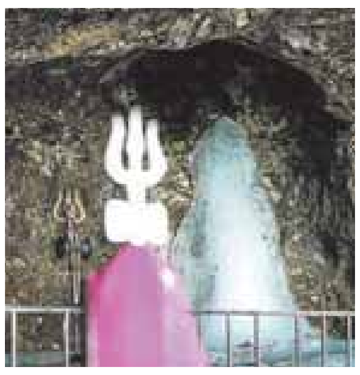

श्रीनगर (एजेंसी)। अमरनाथ यात्रा-2025 के लिए रजिस्ट्रेशन आज (15 अप्रैल) से शुरू हो गए थे। श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 220 रुपए रखी गई है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 600 से ज्यादा बैंकों में किया जा सकता है।इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त (रक्षाबंधन) तक (39 दिन) चलेगी।

वनवासी मजदूर भाई-बहनों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने किया अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 7वें अधिवेशन का शुभारंभ

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 7वें अधिवेशन के शुभारंभ सत्र में सम्बोधित करते हुए कहा कि मजदूर भाई-बहनों की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए भोपाल में विभागों से समन्वय कर काम किया जाएगा। वनवासी भाई-बहनों तथा सभी वर्ग की बेहतरी के लिए कार्य करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सरकार ने इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4800 मजदूर भाई-बहनों के 224 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान करवा दिया है। रतलाम की सज्जन मिल के मजदूरों का बकाया भुगतान भी शीघ्र करवा दिया जाएगा। सरकार की ओर से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए औद्योगिक निवेश के लिए संभागीय स्तर पर रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित कर उद्योगपतियों के साथ अनुबंध किए गये हैं। भोपाल में 9वीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की गयी। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में प्रदेश में उद्योगों को बढावा देने और रोजगार के अवसर तलाशने के कार्य किए गए हैं। प्रदेश में रोजगारमूलक उद्यम स्थापित करने वाले उद्योगपतियों को जमीन आवंटन, विद्युत बिल में छूट देते हुए 70 प्रतिशत तक सरकार द्वारा सबसिडी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश के हित में करेंगे काम, और काम के लेंगे पूरे दाम, यह भारतीय मजदूर संघ का नारा है। सरकार की ओर से देशहित में काम करने वाले मजदूरों को उनका पूरा हक दिया जाएगा। वस्त्र उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों को प्रति मजदूर 5 हजार रुपए प्रति माह अनुग्रह राशि देने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अलीराजपुर क्षेत्र के मजदूर भाई-बहन काम की तलाश में गुजरात राज्य की सूरत स्थित हीरा फैक्ट्री में कार्य पर जाते हैं, इसके लिए अब अलीराजपुर में ही हीरा फैक्ट्री के माध्यम से रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

गंभीर बीमारी के समय गरीबों/मजदूरों के उपचार के लिये एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से अन्यत्र भेजने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। गरीबों के उपचार के लिये प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में निजी चिकित्सालयों में भी उपचार की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि धार और झाबुआ जिले में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे वनवासी जिलों में पढ़ाई एवं उपचार की बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सके। सरकार द्वारा गरीब महिला, किसान, युवा सभी वर्गों के लिए प्राथमिकता से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना अन्तर्गत शिल्पकार, मिस्त्री, बढ़ई सभी वर्गों को रोजगार स्थापित करने में सरकार द्वारा प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

मजदूर भाई-बहनों के कल्याण के लिए संबल योजना संचालित है। संबल योजना अन्तर्गत सभी मजदूर भाई-बहन अपना पंजीयन अनिवार्य रुप से करवाएं। योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि योजनाओं में लाभान्वित किया जा रहा है। परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार के संबल के लिए अनुग्रह राशि दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। संबल योजना में रतलाम जिले के 4 लाख 92 हजार मजदूरों का पंजीयन किया जा चुका है। योजना में पुनः सर्वे कराया जाकर वंचित रहे शेष पात्र हितग्राहियों को पक्के मकान प्रदान किए जाएंगे।

खेती के लिए अच्छी खबर, सामान्य से बेहतर रहेगा मानसून, इस साल जमकर बरसेंगे बादल : मौसम विभाग

105 प्रतिशत बारिश की उम्मीद, अल नीनो का खतरा नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को बताया कि इस बार जून से सितंबर तक मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा। मौसम विभाग 104 से 110 फीसदी के बीच बारिश को सामान्य से बेहतर मानता है। यह फसलों के लिए अच्छा संकेत है। आईएमडीके प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि 2025 में 105 प्रतिशत यानी 87 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। 4 महीने के मानसून सीजन के लिए लॉन्ग पीरियड एवरेज (एलपीए) 868.6 मिलीमीटर यानी 86.86 सेंटीमीटर होता है। यानी मानसून सीजन में कुल इतनी बारिश होनी चाहिए।

सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान: मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल मराठवाड़ा और उससे सटे तेलंगाना में।

सामान्य से कम बारिश का अनुमान: बिहार, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में। मानसून 1 जून के आसपास केरल के रास्ते आता है। 4 महीने की बरसात के बाद यानी सितंबर के अंत में राजस्थान के रास्ते मानसून की वापसी होती है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 22°c
न्यूनतम 16°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 16 अप्रैल 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

बढ़ते तापमान को लेकर अलर्ट, गंभीर रोगों का बढ़ सकता है खतरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। दिल्ली-एनसीआर में पारा अभी से 40 पार करने लगा है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों ने पहले से ही अलर्ट किया है कि इस साल की गर्मी कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। साल 2025 का फरवरी महीना पहले से ही 125 साल में तीसरा सबसे गर्म फरवरी रहा है। अप्रैल की शुरुआत में ही जिस तरह की गर्मी पड़ रही है उसने विशेषज्ञों की चिंता और भी बढ़ा दी है।

हीट स्ट्रोक और गर्मी के कारण होने वाली समस्याओं को देखते हुए कई राज्यों ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसी क्रम में तेलंगाना ने

● तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला लू को ''राज्य विशेष आपदा' घोषित किया

विशेष कदम उठाते हुए लू को 'स्टेट स्पेसिफिक डिजॉस्टर' घोषित किया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि हीटस्ट्रोक से पीड़ित परिवारों को राहत प्रदान की जा सके। नए सरकारी आदेश के तहत लू हीट स्ट्रोक से मरने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। तेलंगाना सरकार ने जारी आदेश में कहा, राज्य सरकार ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पीड़ितों के परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से हीटवेव/सनस्ट्रोक को अब से राज्य विशेष आपदा घोषित करने का निर्णय लिया है।

हार्ट और किडनी पर पड़ सकता है असर– गर्म मौसम और हीटवेव किसी को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे-जैसे आपका शरीर बढ़ते तापमान के कारण गर्म होता जाता है, आपकी रक्त वाहिकाएं फैलने लगती हैं, जिससे रक्तचाप कम हो जाता है। इसके कारण आपके दिल को पूरे शरीर में रक्त का संचार करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ये मौसम हृदय के मरीजों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
इसी तरह हीटवेव का आपकी किडनी पर भी नकारात्मक असर हो सकता है, वहीं जिन लोगों को पहले से ही किडनी की दिक्कत है उन्हें और भी सावधान रहना चाहिए। अत्यधिक गर्मी के संपर्क में रहने वाले लोगों में इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन, किडनी इंजरी होने या किडनी में पथरी होने का खतरा काफी बढ़ जाता है।

मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी का एक्शन

राहुल-सोनिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल 25 अप्रैल को सुनवाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल है।
इस केस में 12 अप्रैल को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई थी। ईडी ने 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। 661 करोड़ की इन अचल संपत्तियों के अलावा एजेएल के 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को ईडी ने नवंबर 2023 में अपराध की आय को सुरक्षित करने और आरोपी को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क किया था।

बंगाल हिंसा पर खुफिया एजेंसियों ने खोले राज

● बांग्लादेशी जिहादी, विदेशी फंडिंग... कैसे रची गई थी हिंसा की प्लानिंग?

कोलकाता (एजेंसी)। वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर बंगाल में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों को चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस हिंसा के पीछे बांग्लादेशी जिहादियों व आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला टीम (एबीटी) का हाथ हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, भारत-बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों में एबीटी के स्लीपर सेल सक्रिय हैं, जो लंबे समय से इस घटना की योजना बना रहे थे। कुछ माह पहले ही एबीटी के तीन आतंकियों को इसी जिले से असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसमें से

दो बांग्लादेशी थे।

तीन महीनों से चल रही थी प्लानिंग– सूत्रों की मानें तो इस हिंसा की साजिश लंबे समय से रची जा रही थी। पिछले तीन महीनों से इस घटना को अंजाम देने की योजना बना रही थी। इसके लिए विदेशों से फंडिंग की गई थी। शुरुआती तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों को जो सबूत मिले हैं, वह इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि शुरू में रामनवमी की तारीख तय थी। हालांकि, सख्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण चीजें बदल गईं और फिर वक्फ संशोधन कानून की आड़ में हिंसा की साजिश रची गई। जांच एजेंसी को इस बात का भी अंदेशा है कि यह स्लीपर सेल मुर्शिदाबाद के अलावा भारत-बांग्लादेश सीमा के अन्य सीमावर्ती भारतीय जिलों के भीतर भी इसी तरह की हिंसा को अंजाम देने की फिराक में है।

● नाव में सवार होकर भारत में घुसे 24 बांग्लादेशी, पुलिस ने की गिरफ्तारी; खुल सकते हैं बड़े राज– महानगर से सटे दक्षिण 24 परगना जिले के भारतीय सुंदरबन क्षेत्र में नाव के जरिये घुसपैठ करने वाले 24 बांग्लादेशी नागरिकों पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें 11 महिलाएं, नौ पुरुष और चार बच्चे शामिल हैं। सुंदरबन तटीय थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने के बाद सुंदरबन के चिलमारी जंगल से सटे इलाके में छापेमारी की। वहां से 24 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि वे सभी बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में घुसे हैं। ये घुसपैठी बांग्लादेश से जलमार्ग द्वारा नाव पर सवार होकर भारतीय सीमा में प्रवेश कर बंगाल पहुंच गए। पुलिस ने सूत्रों से सूचना मिलने के बाद मंगलवार को यह कार्रवाई की। गिरफ्तार लोगों को बुधवार को अलीपुर अदालत में पेश किया जाएगा। दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर पुलिस जिला अधीक्षक पलाश चंद्र धाली ने कहा कि 24 लोगों के समूह में से किसी के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। पूछताछ के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि वे बांग्लादेश से बंगाल में घुसपैठ किए हैं।

अमेरिकी टैरिफ के जवाब में चीन का फैसला

बोइंग जेट की डिलीवरी लेने से इनकार किया

बीजिंग (एजेंसी)। चीन ने अपनी एयरलाइन कंपनियों को अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से नए विमानों की डिलीवरी नहीं लेने के आदेश दिए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग ने अमेरिका में बनने वाले विमान के पार्ट्स और डिवाइसेस की खरीद रोकने का आदेश भी दिया है। चीन ने यह

आदेश अमेरिका के 145 प्रतिशत टैरिफ के जवाब में जारी किया है। बोइंग एयरप्लेन एक अमेरिकी कंपनी है, जो एयरप्लेन, रॉकेट, सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट और मिसाइल बनाती है। कंपनी की स्थापना 15 जुलाई 1916 को विलियम बोइंग ने की थी। कई देशों की एयरलाइंस कंपनियां बोइंग के बनाए गए प्लेन का इस्तेमाल करती हैं। चीन ने अमेरिका के साथ बढ़ती ट्रेड वॉर के बीच 7 कीमती धातुओं (रेयर अर्थ मटेरियल) के निर्यात पर भी रोक लगा दी है।

एम्स ऋषिकेश दीक्षांत समारोह में जेपी नड्डा ने कहा

देश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकता

ऋषिकेश (एजेंसी)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स ऋषिकेश में आयोजित पांचवें दीक्षांत समारोह में शामिल

होकर 434 मेडिकल छात्रों को अपने हाथों से उपाधि दी। जिसके तहत 14 मेडिकल छात्रों को गोल्ड, एक छात्रा को सिल्वर और एक छात्रा को कांस्य पदक से नवाजा। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। एम्स ऋषिकेश के 434 मेडिकल छात्रों को दी गई उपाधि : एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया।

तीन महीने तक 'डिजिटल अरेस्ट' कर वसूले थे 7.67 करोड़, 4 गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 'डिजिटल अरेस्ट' से संबंधित मामले में कथित रूप से शामिल चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सीबीआई प्रवक्ता के अनुसार, 'ऑपरेशन चक्र-वी' के तहत 12 स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान के बाद मुंबई और

मुरादाबाद से दो-दो लोगों को गिरफ्तार किया।
सीबीआई ने राजस्थान सरकार के अनुरोध पर 'डिजिटल अरेस्ट' मामले की जांच शुरू की। साइबर पुलिस स्टेशन झुंझुनू में यह केस दर्ज था। पीड़ित को विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के फर्जी अधिकारी के रूप में साइबर अपराधियों ने तीन महीने से अधिक समय तक डिजिटल रूप से हिरासत में रखा था। इस अवधि के दौरान पीड़ित से 42 बार वसूली की गई। यह राशि 7.67 करोड़ रुपये थी।

कोटा में स्टेट हाईवे 70 पर भीषण हादसा, बाइक सवार एक परिवार के चार लोगों की मौत

कोटा (एजेंसी)। जिले में कोटा से श्योपुर जा रहे स्टेट हाईवे नंबर 70 पर मंगलवार सुबह करीब आठ बजे भीषण सड़क

हादसा हो गया। सुल्तानपुर थाना इलाके में तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार एक परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। इनमें पति-पत्नी और बेटा शामिल हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन पलट गए और सड़क से नीचे उतर खाई में गिर गए।

संसद में बदले समीकरण, यूसीसी पर आगे बढ़ी मोदी सरकार

● विपक्षी दलों का वक्फ बिल पर समर्थन, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तेजी दिखाएगा केंद्र

नई दिल्ली (एजेंसी)। वक्फ कानून के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) अब केंद्र सरकार के टॉप एजेंडे में है। सूत्रों के मुताबिक संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल को मिले समर्थन को देखते हुए सरकार ने यूसीसी पर काम आगे बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल, लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से पीछे रह गई। बहुमत के लिए वह जनता दल-यूनाइटेड (जेडीयू) और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) पर निर्भर है। संसद के अंकगणित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विवादित मुद्दे किनारे रखने की रणनीति अपनाई थी। हालांकि, वक्फ बिल को जेडीयी और टीडीपी के अलावा बायएसआरसीपी और बीजेडी जैसे दलों का भी समर्थन मिला था। इसके बाद सरकार यूसीसी पर आगे बढ़ने का मन बना चुकी है।

इसके अलावा तमिलनाडु में एआईएडीएमके को साथ लेने के बाद भाजपा परिसीमन और भाषा जैसे मुद्दों को किनारे लगाना चाहती है। तमिलनाडु में अगले साल चुनाव हैं। इन मुद्दों से डीएमके को फायदा हो सकता है।

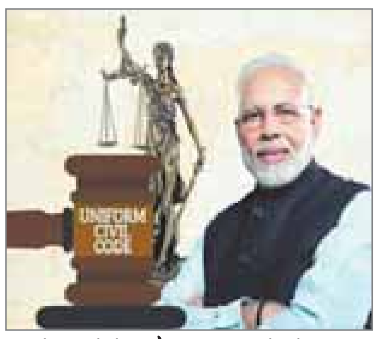

मोदी बोले– मैं यूसीसी को सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को हरियाणा में कहा- जब-जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं। कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड डंके की चोट पर लागू हुआ। संविधान को जेब में लेकर बैठे कांग्रेस के लोग उसका विरोध कर रहे हैं।

● महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

जजों को सावधान रहना चाहिए ...

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से जुड़े मामलों में जजों को अनुचित टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जजों को सावधान रहना चाहिए और वे जमानत दे सकते हैं, लेकिन ऐसी टिप्पणियां क्यों करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक मामले के संबंध में अपने द्वारा शुरू किए गए एक स्वतः संज्ञान मामले में की है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादास्पद आदेश को पूरी तरह से असंवेदनशील बताया और कहा हम यह बताने में दर्द महसूस कर रहे हैं कि यह निर्णय संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है। सुनवाई के दौरान मंगलवार को बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एक और हालिया अवलोकन के लिए अपवाद लिया कि महिला ने खुद परेशानी को आमंत्रित किया था और कथित बलात्कार के लिए जिम्मेदार थी। पीठ ने कहा कि हालांकि जमानत देने प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर न्यायाधीश का विवेक पर है, लेकिन उसे शिकायतकर्ता के खिलाफ इस तरह की अनुचित टिप्पणियों से बचा जाना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आरजेडी और कांग्रेस की बैठक

● तेजस्वी बोले-अमित शाह नीतीश को सीएम फेस नहीं बताते ● दिल्ली में राहुल-खड़गे के साथ 45 मिनट मीटिंग, निशांत का जवाब-पिता ही होंगे मुख्यमंत्री

पटना (एजेंसी)। दिल्ली में मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आरजेडी और कांग्रेस की मीटिंग हुई। यह मीटिंग लगभग 45 मिनट चली। बैठक के बाद खड़गे आवास के बाहर मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि, जो भी चीजें हैं, मिलकर बैठकर तय हो जाएंगी।

सीएम फेस के सवाल पर उन्होंने कहा- 'बातचीत से सब फाइनल होगा। आपलोग चिंता न करें।' कितने सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि 'इस बार बिहार में हमारी सरकार बनेगी यह तय है।'

बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहें। वहीं राजद की ओर से तेजस्वी यादव के साथ-साथ राजद सांसद मनोज झा, और संजय यादव भी मीटिंग में शामिल हुए।

राजेन्द्र शर्मा

(लेखक संगीत समीक्षक एवं उप्र सरकार में अधिकारी हैं)

संकट मोचन संगीत समारोह की 102वीं उजास

भारतीय शास्त्रीय संगीत में देश के अपनी तरह के इकलौते संकट मोचन संगीत समारोह वाराणसी की छटा एक बार फिर से सामने है। इस वर्ष 16 से 21 अप्रैल तक वाराणसी के उसी प्रांगण में यह समारोह हमेशा की तरह साकार होगा, जिसे देखने के लिए देश-दुनिया से लोग विश्वनाथ की नगरी में दाखिल होते हैं। एक तरफ ऐतिहासिक नगरी का लावण्य तो दूसरी तरफ पूरे छह रोज़ तक कलाकारों की रस वर्षा। उस पर उन कलाकारों को निःशुल्क सुनने मिलना- जो प्रथम श्रेणी के सितारा फ़नकार माने जाते हैं। वाराणसी के संकट मोचनमंदिर प्रांगण में प्रतिदिन रात्रि ठीक 7:30 इसका शुभारम्भ होगा।

वाराणसी में हनुमान जयंती के उपलक्ष में होने वाले 102 वें संकट मोचन संगीत समारोह की महत्ता इसकी प्राचीनता के कारण भी है। इस समारोह के अलावा मध्य प्रदेश के तानसेन समारोह का नाम आता है जो 101 वर्ष से आयोजित हो रहा है। वाराणसी में दुर्गाकुंड क्षेत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निकट स्थित मंदिर में रखी भगवान हनुमान की मूर्ति को बाबा संकटमोचन कहा जाता है। कहा जाता है कि इसे कवि गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा था।

एक सौ एक वर्ष की अपनी अनवरत यात्रा में यह आयोजन संगीत के लोकपर्व के रुप में स्थापित हो चुका है। यहां केवल श्रोता होते हैं। बाकी सब कुछ हनुमानजी ही होते हैं। कवि व्योमेश शुक्ल कहते हैं कि इस समारोह में कोई किसी को बुलाता नहीं है,हनुमान जी ही असल और एकांत श्रोता हैं।

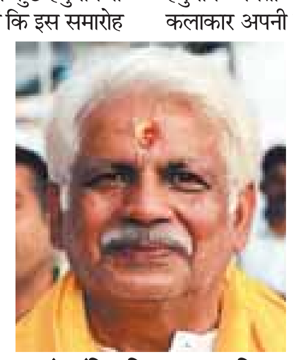

महंत पंडित विशम्भरनाथ मिश्र

जानकार बताते हैं कि बनारस में शास्त्रीय संगीत के कलाकारों के दो मुहल्ले कबीर चौरा और रामापुरा शास्त्रीय संगीत के कलाकारों के मौहल्ले होते थे,जो आज भी हैं, परन्तु एक सौ दो साल पहले कलाकारों के पास आज जैसे अवसर नही होते थे। उस समय कबीर चौरा और रामापुरा में कलाकार अपनी साधना में लीन रहते और राजा महाराजा, नवाब और बड़े लोग उनके जीवन यापन की व्यवस्था करते, जिसके एवज में कलाकार इन लोगों के दरबारों में अपनी कला का प्रदर्शन करते। एकाएक संकट मोचन मंदिर के महंत अमरनाथ मिश्र के मस्तिष्क में यह ख्याल आया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की महान परम्परा जब राजा महाराजा, नवाबों और बडे लोग की दरबार और बैठकों तक सीमित रहेगी तो आम जनमानस भारतीय शास्त्रीय संगीत से कैसे भिज्ञ हो सकेगा।

महंत अमरनाथ मिश्र ने तय किया कि हर बरस हनुमान जयंती के अवसर पर जनमानस के लिए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेगें और कलाकारों कोई पारिश्रमिक भी नही लेगें। पहला आयोजन वर्ष 1923 में हनुमान जयंती के अवसर पर किया गया। यह परम्परा आज एक सौ दो वर्ष तक जारी है। यहां कलाकार 'हाजिरी' लगाते हैं। शुरू में यहां पहले रामायण सम्मेलन होता था फिर संगीत सम्मेलन। शुरुआती दौर में यह दिन का होता था, अब छह दिन का यह आयोजन होता है। इस वर्ष की सूची में प्रतिदिन प्रतिनिधि कलाकारों की संख्या 8 दर्ज है। सहायक कलाकारों को भी शामिल कर लें तो यह संख्या 25 बनाती हैं। 102वें आयोजन में 11 पद्मश्री/पद्म विभूषण अवार्डी कलाकार शिरकत करेंगें। महंत विशम्भर नाथ मिश्र ने ऐसे 16 कलाकारों को पहली समारोह में हाज़िरी लगाने का अवसर देकर युवा श्रोताओं में उत्सुकता बढ़ा दी है। इन 16 कलाकारों में श्रीमती जननी मुरली (भरतनाटयम), लावण्या शंकर (भरतनाटयम), रोहित पवार (कथक),विवेक पाण्डया (तबला), पंडित राजेन्द्र सेजवार (गायन), स्नेहा शंकर(गायन), नयनिका घोष (कथक),अभिषेक लाहिडी (सरोद),पंडित साहित्य कुमार नाहर (सितार) और शाइना बनर्जी (सितार), सोहनी राय चौधरी (गायन), राजेश शाह (सितार) प्रमुख है। इस बारे में महंत विशम्भर नाथ मिश्र कहते हैं कि इस आयोजन का एक बड़ा उद्देश्य भविष्य के बड़े डे कलाकारों की खोज कर, उन्हें मंच प्रदान करना है। इसी प्रांगण में मंच पर अपनी कला पेश करने वाला कलाकार जब अपनी प्रस्तुति ख़त्म कर मंच से नीचे उतरता है तो अपना सारा गौरव एकतरफ रख कर अन्य नवोदित कलाकारों को विद्यार्थियों की तरह सुनता दिखाई देता है।

संगीत मार्तंड - पंडित जसराज ने एक बार कहा था कि पैसा, पारिश्रमिक और पद अपनी जगह है। लेकिन संकट मोचन संगीत समारोह में प्रस्तुति का जो आनंद है वह सारे आकर्षणों से परे है। इस समारोह में सुगम संगीत को भी मान्यता है। शास्त्रीय संगीत में उत्तर भारतीय के साथ दक्षिण भारतीय विधाएँ भी जोड़ी गई हैं। कुछ अप्रचलित या कहिये प्रचलन से बाहर होती विधाएँ भी आकर्षण होंगी।

फिलहाल संकट मोचन परिसर में रोमांच है -और 16 अप्रैल की शाम की समारोह का पहला सुर बांसुरी सम्राट पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के वादन से गूंजेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जे.के. जैन के निधन पर दुख व्यक्त किया

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्यप्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री जे.के. जैन के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्री जैन अपने सेवाकाल में कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहे। उनके असामयिक निधन से प्रदेश और समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल से पुण्यात्मा को शांति और स्व. जैन के शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

जनता में खुशहाली लाने के लिए बनाए जाएं आनंद ग्राम : निदेशक गंगराड़े

भोपाल (नप्र)। राज्य आनंद संस्थान के निदेशक श्री प्रवीण कुमार गंगराड़े ने कहा कि लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए ग्राम स्तर पर अधिक से अधिक आनंद ग्राम स्थापित किए जाएं। उन्होंने यह बात खरगोन में आयोजित आनंद क्लब सदस्यों, आनंदम सहयोगियों एवं आनंदकों की समीक्षा बैठक में कही।

निदेशक श्री गंगराड़े ने कहा कि खरगोन जिले में आनंद विभाग की गतिविधियां सराहनीय हैं, लेकिन अभी और संभावनाएं हैं। उन्होंने स्वयं आनंदित रहते हुए दूसरों को भी आनंद संस्थान से जोड़ने की अपील की। विशेष रूप से आनंद, अल्पविराम जैसी गतिविधियों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हेप्पीनेस वालंटियर्स की भूमिका को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया।

''आनंद की ओर'' कार्यक्रम

उन्होंने बताया कि राज्य आनंद संस्थान द्वारा आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में 'आनंद की ओर' सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों पर आधारित था। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को एक आनंदमयी जीवन शैली अपनाने के लिये प्रेरित करना रहा।वन विद्यालय झाबुआ में भी आनंद की ओर कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों ने उत्साह और उमंग के साथ सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को मानव मूल्यों पर आधारित जीवन जीने की कला से अवगत कराया गया। चर्चा में यह समझाया गया कि किस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में सजगता, संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर जीवन को तनावमुक्त, शांतिपूर्ण और आनंदमय बना सकते हैं। सत्र में छोटे-छोटे पर्यवेक्षणों के माध्यम से अपने भीतर झांकने और अपने व्यवहार में सुधार लाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। विद्यार्थियों ने प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से जीवन जीने की प्रक्रिया को गहराई से समझा।

आनंद शिविर

राज्य आनंद संस्थान द्वारा शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए पंचगनी, महाराष्ट्र में 22 से 25 अप्रैल तक चार दिवसीय आनंद शिविर का आयोजन किया जाएगा।

सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य अतीत के स्वर्णिम पृष्ठ का प्रकटीकरण : सीएम डॉ. यादव

कार्यक्रम में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया, रेखा गुप्ता और डॉ. मोहन यादव

भोपाल/दिल्ली (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश की राजधानी में लाल किले की प्राचीर पर ऐतिहासिक महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का मंचन उस युग को जीवंत करने का प्रयास है। यह विश्व में भारत द्वारा सुशासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने की दिशा में कारगर रहेगा।

फिल्मों के निर्माण और डिजिटल युग के बावजूद प्राचीन नाट्य परम्परा से परिचित करवाने वाले इस महानाट्य के अंश अविस्मरणीय रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को नई दिल्ली में तीन दिवसीय महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य के मंचन के समापन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में महानाट्य के कलाकारों का सम्मान भी किया गया। इसमें अनेक जनप्रतिनिधि, धर्म और आध्यात्म क्षेत्र की हस्तियां और बड़ी संख्या में कला प्रेमी उपस्थित थे।

विरासत से विकास के मंत्र पर हो रहा है कार्य- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विरासत के संरक्षण के साथ विकास का मंत्र दिया है। वास्तव में वर्तमान काल अद्भुत है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं को प्रधान सेवक मानते हैं। आज भारत की गरिमा विश्व में निरंतर बढ़ रही है। एक समय

था जब सम्राट विक्रमादित्य ने न्याय, वीरता और सुशासन के महत्व को स्थापित किया। सम्राट विक्रमादित्य के युग को पुनः महानाट्य के माध्यम से जीवंत किया गया है। सम्राट विक्रमादित्य के जीवन के विभिन्न पक्षों को महानाट्य के माध्यम से आमजन सामने लाने का अभूतपूर्व कार्य हुआ है।

नाट्य विधा प्राचीन विधा है, इसका आज भी है महत्व

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नाट्य विधा एक प्राचीन विधा है। आज के डिजिटल युग में भी इस विधा का महत्व बरकरार है। फिल्मों के निर्माण के साथ अनेक माध्यमों से कला और संस्कृति के दर्शन होते हैं लेकिन महानाट्य से सम्राट विक्रमादित्य के जीवन और शासन काल को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह महानाट्य हमारे इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ और गौरवशाली अतीत से परिचय करवाता है।

विशिष्ट अतिथियों का मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने माना आभार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिल्ली में महानाट्य के मंचन को देखने के लिए पधारे राज्य सभा के उप सभापति हरवंश सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, स्वामी अचलानंद जी, मध्यप्रदेश के मंत्रीगण राकेश सिंह, प्रद्युम्न सिंह तोमर, नरेंद शिवाजी पटेल, दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद का उपस्थिति के लिए आभार माना और संस्कृति मंत्रालय एवं विक्रमादित्य शोध पीठ के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

150 साल बाद बाग प्रिंट में लौटी 'नील' की रौनक

गौहर महल में इंडिगो रंग से बने बाग प्रिंट के कपड़े बने आकर्षण का केंद्र

भोपाल (नप्र)। भोपाल के गौहर महल में 11 से 20 अप्रैल तक चल रहे बाग महोत्सव में खूबसूरत इनोवेशंस देखने को मिल रहे हैं। प्राकृतिक रंगों से किए जाने वाले बाग प्रिंट में इस बार दो नए रंग जुड़ गए हैं। पहला है अकाव का रंग, जो लोहे में जमी जंग पर हरड़ के उपचार से तैयार किया जाता है। दूसरा रंग है

नील (इंडिगो), जो नील की पत्तियों के फरमेंटेशन और गुड़ व चूने के विशेष प्रभाव से तैयार किया गया है। इंडिगो रंग बनाने की यह प्रक्रिया बहुत प्राचीन है, जिसे हुनरमंद कारीगर उमर फारूक खत्री ने फिर से जीवित किया है।

उमर के परदादा, बाग प्रिंट के जनक अली, लगभग 150 साल पहले बाग प्रिंट के कपड़ों में नील की पत्तियों से बने नीले रंग का उपयोग करते थे। कहा जाता था कि यह उस समय लोगों को इतना अधिक पसंद आता था कि वह बाजार में वह सबसे आखिर में आते थे और सबसे पहले बेचकर चले जाते थे। फिर धीरे धीरे लाल और काला रंग लोग पहनने लगे, तो इसका चलन कम हो गया। अब एक बार फिर बाजार में इंडिगो पौधे की पत्ती से बने कलर के बाग प्रिंट कपड़ा मिल रहा है।

1 महीने में तैयार होता है रंग

मास्टर क्राफ्टमैन उमर ने बताया- बाग प्रिंट में इंडिगो रंग के इस्तेमाल पर मैं 2016 से काम कर रहा हूं। कई बार गलतियां हुईं। पिछले साल तक भी इस रंग में वैसा शेड और टोन पाना मुश्किल था। मगर, अब सफलता मिल गई है।

इंडिगो प्राकृतिक कलर है। इसका पौधे की पत्ती को पानी में गला देते हैं। उसमें बाद में नील का रंग आ जाता है। उसकी प्रोसेस के लिए उसमें चूना डालना पड़ता है। फिर वह चूने के साथ पकता है। तब जाकर उससे डाई करते हैं। पत्ती भिगोने से लेकर तैयार करने में करीब 1 महीने का समय लता है। कपड़े को डाई करके सुखाया जाता है। वह धीरे धीरे नीला हो जाता है। हमारे पिताजी बताते हैं कि हमारे पड़दादा अली जी मार्केट में सबसे आखिर में आते थे और सबसे पहले कपड़ा बेचकर चले जाते थे।

प्रदेश में आज से लू चलेगी, ग्वालियर-चंबल सबसे गर्म रहेंगे

पूर्वी हिस्से में हल्की बारिश ; भोपाल, इंदौर-उज्जैन में तेज गर्मी रहेगी

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में आज 16 अप्रैल से हीट वेव यानी, लू का असर शुरू होगा। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और चंबल संभाग के जिलों में लू चलेगी। इससे पहले मंगलवार को पूर्वी हिस्से के 7 जिले-शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा में कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में मंगलवार को गर्मी का असर तेज रहेगा। यहां पारा 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। बारिश और आंधी की गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी।

रतलाम में पारा 42 डिग्री रहा- प्रदेश में मौसम के दो रंग देखने को मिले। पांढुर्णा, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिंगरौली, अनूपपुर, सीधी, सिवनी, रीवा आदि जिलों में बादल छाए रहे। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई है। दूसरी ओर, प्रदेश के बाकी के हिस्से में गर्मी का असर रहा। रतलाम में दिन का तापमान सबसे ज्यादा 42 डिग्री दर्ज किया गया। शाजापुर-धार में पारा 41 डिग्री, खंडवा में 40.5 डिग्री और नर्मदापुरम में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बड़े शहरों की बात करें तो उज्जैन सबसे गर्म रहा। यहां पारा 41 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में 39.5 डिग्री, इंदौर में 39.7 डिग्री, ग्वालियर में 37.5 डिग्री और जबलपुर में तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

आज मौसम के दो रंग दिखेंगे- मौसम वैज्ञानिक प्रमेंद्र कुमार रैकवार ने बताया कि अगले 2 दिन तक बारिश की गतिविधि रहेगी। 16 अप्रैल को कुछ जिलों में हल्की बारिश होने के आसार हैं, जबकि 11 जिलों में लू का अलर्ट है। 17 और 18 अप्रैल को भी लू चलने की संभावना है।

ऐसा रहेगा अप्रैल का दूसरा पखवाड़ा

तीसरा सप्ताह- उत्तर-पश्चिमी हवाओं के जोर पकड़ने के साथ इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, नर्मदापुरम संभागों में न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूरे प्रदेश में दिन में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। 2 से 3 दिन लू चल सकती है। हल्की बारिश होने की संभावना है।

चौथा सप्ताह- उत्तर-पश्चिमी हवाओं के लगातार जोर पकड़ने के साथ न्यूनतम तापमान पूरे प्रदेश में सामान्य से 3-4 डिग्री अधिक यानि 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। दिन के साथ रातें भी गर्म हो जाएंगी। ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग में पारा 43-45 डिग्री जबकि इंदौर, उज्जैन-भोपाल सहित बाकी प्रदेश में 41 से 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रह सकता है। बंगाल क्षेत्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से अप्रैल के आखिरी में 3 से 4 दिन तक लू का असर रह सकता है।

राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निर्माण के लिये प्रारंभ हुई कार्यशाला

भोपाल (नप्र)। राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या की रूप रेखा निर्माण के लिये 3 दिवसीय कार्य शाला का शुभारंभ मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री अलकेश चतुर्वेदी ने मंगलवार को भोपाल के लेक-व्यू अशोका में दीप प्रज्ज्वलित कर के किया।

कार्यशाला में बच्चों का सर्वांगीण विकास, कौशल विकास और आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा जैसे उद्देश्य बिंदुओं पर विचार मंथन के बाद प्राप्त सुझावों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति को प्रेषित किया जाएगा। इसके बाद राज्य की पाठ्यचर्या का निर्माण भी किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये टास्क फोर्स का गठन किया है। कार्य शाला में 11 कार्य समूहों का गठन किया गया है। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या निर्माण समिति के प्रतिनिधि, प्रदेश पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति के सदस्यगण, राज्य शिक्षा केंद्र विषय समन्वयक एवं अन्य सहयोगी संस्थाएं के विषय विशेषज्ञ सहभागिता कर रहे हैं। कार्य शाला में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और शिक्षा शास्त्र जैसे विषयों के संबंध में विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त किये जायेंगे।

संजय नगर में 10 घरों में करंट फैला, युवक की मौत

डीपी में शॉर्ट-सर्किट से 5-6 घरों में टीवी-फ्रिज-पंखे खराब ; बिजली कंपनी से लोग नाराज

भोपाल (नप्र)। भोपाल के शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र के संजय नगर में मंगलवार सुबह 7 बजे बिजली विभाग के डीपी में शॉर्ट सर्किट हो गया। इससे करीब 10 से ज्यादा घरों में करंट फैल गया। इस दौरान सतीश ककोटे (25) नाम के युवक की करंट लगने से मौत हो गई।

घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में बिजली विभाग के प्रति भारी गुस्सा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई है। इससे पहले भी कई बार घरों में करंट फैलने की घटनाएं

सामने आ चुकी हैं, लेकिन बिजली विभाग की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया।

घर से निकल रहा था, दरवाजा छूने पर करंट

भाई रामू ककोटे ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे जब सतीश अपने घर से बाहर निकल रहा था। उसने दरवाजा पकड़ा तो जोरदार करंट लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में सतीश के घर के टीवी, पंखे और कूलर भी जल गए। कई अन्य घरों में भी इसी तरह का नुकसान हुआ है।

शाहजहांनाबाद थाना प्रभारी यूपीएस चौहान ने बताया कि घटना डीपी में फॉल्ट के कारण हुई है। सतीश के शव का पोस्टमॉर्टम् कराकर परिजन को सौंप दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

स्थानीय लोगों ने गिनाए पुराने हादसे

इलाके के शफीक रहमान ने बताया कि इससे पहले भी चार बार ऐसे ही हादसे हो चुके हैं। कई बार शिकायत के बाद भी केवल दिखावटी मरम्मत होती है। इससे पहले कई बार खंबे से करंट लगकर गाय, भैंस और बकरी भी मार चुकी हैं।इसके अलावा मोहम्मद इरशाद ने भी बताया कि उनके घर समेत करीब पांच-छह घरों में टीवी, फ्रिज और पंखे खराब हो गए हैं।

बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप

वार्ड-11 के पूर्व पार्षद मेवालाल केनर्जी ने कहा कि घटना की पूरी जिम्मेदारी एमपीईबी की है। क्षेत्र में हमेशा डीपी में आग लगती रहती है। कई बार सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। अधिकारियों की लापरवाही से एक युवक की जान चली गई, ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

भोपाल के कोलार में सड़कों को देखने पहुंचे विधायक शर्मा

सीआई चौराहे से बंसल हॉस्पिटल तक लगेंगे सिग्नल, बंजारी स्टेडियम का लिया जायजा

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कोलार रोड स्थित सीआई चौराहा से बंसल हॉस्पिटल के बीच ट्रैफिक सिग्नल भी लगेंगे। विधायक रामेश्वर शर्मा ने मंगलवार सुबह सड़क का निरीक्षण कर अफसरों को यह निर्देश दिए। विधायक कोलार की निर्माणाधीन सड़कों को देखने पहुंचे थे। उन्होंने बंजारी स्थित स्टेडियम भी देखा।

विधायक शर्मा ने सीआई चौराहे से बंसल हॉस्पिटल अस्पताल तक बन रहे फोरलेन 'अवध मार्ग' का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज सहित कनेक्टिंग रोड के निर्माण संबंधी निर्देश दिए। विधायक ने केरवा डेम से सेमरी तक बनने वाले फोरलेन सड़क निर्माण कार्य एवं बंजारी के इनडोर स्टेडियम का भी निरीक्षण किया।

40 करोड़ में बन रही सड़क- बता दें कि बंसल हॉस्पिटल तिराहे से कोलार रोड स्थित सीआई चौराहे तक पीडब्ल्यूडी 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 40 करोड़ रुपए से कर रहा है। दानिश चौराहा और सीआई चौराहे के पास कुछ काम बचा है, जिसे विधायक ने पूरा करने को कहा।

यह भी निर्देश दिए

- स्ट्रीट लाइट का कार्य जल्द शुरू किया जाए।
- सड़क के साथ ड्रेनेज की व्यवस्था सुदृढ़ हो।
- कनेक्टिंग रोड का निर्माण भी गति लाने के निर्देश दिए।
- विराशा हाईट-अग्रसेन चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाए।
- विराशा हाइट कालीबाड़ी मंदिर के पास कलियासोत नदी पर इसी मार्ग पर बनने वाले पुल को लेकर भी निर्देश दिए।
- केरवा डेम से सेमरी तक बनने वाले फोरलेन सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाना है।
- बंजारी में बन रहे मुखर्जी स्टेडियम को देकर विभिन निर्देश दिए।

विधायक ने कहा- सड़कों को बेहतर बना रहे

विधायक शर्मा ने कहा कि क्षेत्र की प्रगति में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यह अवध मार्ग मुखर्जी नगर कोलार के यातायात की सुगमता को और अधिक बेहतर कर रहा है। मुखर्जी नगर कोलार के प्रत्येक क्षेत्र को फोरलेन अथवा सिक्स लेन से जोड़ा जाए। केरवा डेम से सेमरी तक बनने वाली फोरलेन सड़क अपने निर्माण के बाद नागरिक सुविधा को और सुगम बनाएगी। साथ ही क्षेत्र की प्रगति से नागरिक प्रगति के अवसरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी।

संपादकीय

कांग्रेस का 'नया राष्ट्रवाद'

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद में हुए दो दिनी (प्लेनरी) अधिवेशन में व्यक्त 'गुजरात विजय' का संकल्प कितना और कैसे पूरा होगा, यह देखने की बात है, लेकिन इस अधिवेशन पारित प्रस्ताव में पहली बार पार्टी ने अपने 'राष्ट्रवाद'का खुलासा किया। यूं भाजपा और संघ के राष्ट्रवाद को विभाजनकारी मानने वाली कांग्रेस ने कहा कि उसका राष्ट्रवाद समाज को जोड़ने वाला है, जबकि बीजेपी और आरएसएस का छद्म राष्ट्रवाद लोगों को विभाजित करना चाहता है। इस दो दिनी अधिवेशन के अंतिम दिन पारित प्रस्ताव को कांग्रेस ने 'न्याय पथ' नाम दिया है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस अब सपा, बसपा जैसी पार्टियों के 'सामाजिक न्याय' के मुद्दे पर ही आगे बढ़ना चाहती है। अधिवेशन में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोगों के मुद्दों की समानता के आधार पर इंडिया गठबंधन की स्थापना की और उसे कायम रखा। हम इस प्रयास को जारी रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। साथ ही देश में 'एक देश, एक चुनाव' जैसी संविधान विरोधी कोशिशो को सफल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अहम बात कांग्रेस द्वारा पिछले दरवाजे से उस राष्ट्रवाद का स्वीकार है, जो भाजपा और आरएसएस का कोर एजेंडा है। फर्क इतना है कि कांग्रेस ने अपने राष्ट्रवाद को समावेशी राष्ट्रवाद कहा है। पार्टी द्वारा अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि कांग्रेस की नजर में राष्ट्रवाद के मायने देश की भू-भागीय अखंडता के साथ साथ इस महान भूभाग में रहने वाले लोगों का सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक सशक्तीकरण भी है। पार्टी के मुताबिक कांग्रेस का राष्ट्रवाद समाज को जोड़ने वाला है जबकि बीजेपी-आरएसएस का राष्ट्रवाद समाज को तोड़ने वाला है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद भारत को अनेकता को एकता में पिरोने का है जबकि बीजेपी-आरएसएस का राष्ट्रवाद भारत की अनेकता को खत्म करने का है। इसे और विस्तार से समझाते हुए कांग्रेस ने कहा कि त्याग, बलिदान, बहुलतावाद और उदारवाद का कांग्रेस का रास्ता ही भारतीय राष्ट्रवाद है। यही नहीं कांग्रेस ने आरएसस पर भी सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उसकी विचारधारा संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। हालांकि संघ के उग्र राष्ट्रवाद के बरखिलाफ जनता कांग्रेस के राष्ट्रवाद को कितना स्वीकार करेगी, कहना मुश्किल है। क्योंकि पार्टी अभी तक खुद को सेक्युलरवादी के रूप में पेश करती आई है। दूसरा मुद्दा जातिगणना का भी है। कांग्रेस ने ओबीसी जातिगणना के मुद्दे को हवा देने का निर्णय लिया है। लेकिन इससे खुद को राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली कांग्रेस को खास लाभ नहीं होता। बिहार में जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का यह सवाल वाजिब है कि देश में 75 सालो से एससी, एसटी की जातिगणना हो रही है। लेकिन इससे उनके जीवन में क्या सुधार हुआ। इसका सीधा मतलब है कि जाति की गिनती का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि उनका सामाजिक आर्थिक उत्था न न हो। लेकिन आज कांग्रेस अगर भाजपा से सचमुच पूरी ताकत से लड़ना चाहती है तो उसे अपना संगठनात्मक ढांचा मजबूत करना होगा, इस दिशा में कुछ खास प्रगति नहीं दिखती है। उसे तय करना होगा कि वो कौन सा वोट बैंक है, जिसे वह संवर्द्धित करना चाहती है? वक्फ बोर्ड पर भी उसकी नीति असमंजस से भरी है। कभी वह क्षेत्रीय पार्टियों की तरह व्यवहार करने लगती है तो कभी उसे याद आता है कि वह एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पहले यह तय करे कि उसे करना क्या है और कैसे करना है, तभी ऐसे अधिवेशनों का व्यावहारिक महत्व है। अल्पसंख्यक वोट बैंक बचाने से भी ज्यादा बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने यह है कि उससे टूट चुका बहुसंख्यक हिंदू वोट वापस कांग्रेस की तरफ कैसे लौटे, जो राम जन्म भूमि विवाद के बाद से कांग्रेस से दूर जा चुका है।

राजनीति की आँच पर सुलगता बंगाल

वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर मुस्लिम समुदाय में एक गहरा असंतोष व्याप्त है। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह संशोधन अधिनियम कई मुसलमानों को यह आशंका देता है कि उनके धार्मिक और सामाजिक अधिकारों का अतिक्रमण हो सकता है। बंगाल जैसे राज्य में, जहाँ मुस्लिम आबादी एक महत्वपूर्ण संख्या में है, यह असंतोष स्वाभाविक रूप से व्यापक विरोध में तब्दील हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार-बार आश्वासन दिया कि यह अधिनियम राज्य में लागू नहीं किया जाएगा और अल्पसंख्यक हितों की रक्षा की जाएगी। लेकिन ज़मीनी स्तर पर इन आश्वासनों का कोई विशेष असर नहीं दिखा, और मुस्लिम समुदाय के आक्रोश को शांत करने में प्रशासन विफल रहा।

नजरिया

नृपेन्द्र अभिषेक नृप
लेखक शोधार्थी हैं।

पश्चिम बंगाल की भूमि, जहाँ एक समय कवियों की कलम और क्रांतिकारियों की मशाल से जागरण हुआ करता था, आज राजनीति की चिंगारियों और साम्प्रदायिक धुएँ से घिरी प्रतीत होती है। हाल के दिनों में वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर फैले जनाक्रोश और उसके गर्भ से उपजी हिंसा ने न केवल राज्य की सामाजिक संरचना को झकझोर दिया है, बल्कि इसने शासन की संवेदनशीलता, राजनीतिक दलों की नीयत और समाज की सहिष्णुता पर भी गहरे प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। मुर्शिदाबाद की गलियों में गूँजी गोलियों की आवाज़ें और तीन निर्दोष जानों की क्षति इस बात की भयावह गवाही हैं कि जब सियासत धर्म की ओट में खेलती है, तो सबसे पहले इंसानियत ही घायल होती है।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर मुस्लिम समुदाय में एक गहरा असंतोष व्याप्त है। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह संशोधन अधिनियम कई मुसलमानों को यह आशंका देता है कि उनके धार्मिक और सामाजिक अधिकारों का अतिक्रमण हो सकता है। बंगाल जैसे राज्य में, जहाँ मुस्लिम आबादी एक महत्वपूर्ण संख्या में है, यह असंतोष स्वाभाविक रूप से व्यापक विरोध में तब्दील हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार-बार आश्वासन दिया कि यह अधिनियम राज्य में लागू नहीं किया जाएगा और अल्पसंख्यक हितों की रक्षा की जाएगी। लेकिन ज़मीनी स्तर पर इन आश्वासनों का कोई विशेष असर नहीं दिखा, और मुस्लिम समुदाय के आक्रोश को शांत करने में प्रशासन विफल रहा।

8 अप्रैल से शुरू हुई यह हिंसा तमाम निषेधाज्ञाओं और इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के बावजूद लगातार जारी रही। सार्वजनिक संपत्तियों पर हमले, भीड़ द्वारा आगज़नी और पथराव की घटनाएँ मुर्शिदाबाद के जंगीपुर उपमंडल से लेकर कोलकाता तक फैलीं। यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल धार्मिक असंतोष नहीं, बल्कि सुनियोजित राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल लंबे समय से एक 'सांप्रदायिक कढ़ाही' के रूप में उबल रहा है, जहाँ राजनीतिक दल जानबूझकर धर्म की आग में घी डालने का कार्य करते आए हैं।

इस प्रकरण में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल – सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की भूमिका समान रूप से संदिग्ध और चिंताजनक रही है। टीएमसी जहाँ वक्फ संशोधन के विरोध में मुस्लिम समुदाय को मौन रूप से समर्थन देती दिखी, वहीं बीजेपी ने राम नवमी की धार्मिक शोभायात्राओं को सांप्रदायिक रंग देकर अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश की। राम नवमी के जुलूस, जो पहले धार्मिक उत्सव का प्रतीक थे, अब राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन और उकसावे का माध्यम बन गए हैं। इन शोभायात्राओं में भड़काऊ नारों, हथियारों के प्रदर्शन और समुदाय विशेष को चुनौती देने जैसी घटनाओं ने स्थिति को और विस्फोटक बना दिया।

पुलिस की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में कमज़ोर और निष्क्रिय दिखाई दी। राज्य पुलिस न तो समय रहते हिंसा रोक सकी, न ही अपराधियों पर

प्रभावी कार्रवाई कर सकी। अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा, और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती का आदेश दिया। इससे राज्य प्रशासन की अक्षमता और राजनीतिक दबाव के तहत काम करने की विवशता भी उजागर हुई।

यह स्थिति कोई अचानक उत्पन्न हुई आपदा नहीं है, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें शासन, समाज और राजनीति तीनों की असफलताएँ परिलक्षित होती हैं। पश्चिम बंगाल के कई इलाके, विशेष रूप से मुर्शिदाबाद, आर्थिक दृष्टि से बेहद पिछड़े हैं। यहाँ के लोग बीड़ी बनाने जैसे छोटे-मोटे कार्यों पर आश्रित हैं और पलायन करके अन्य राज्यों में मजदूरी करते हैं। इन परिस्थितियों में जब राजनीतिक दल धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं, तो समाज में आसानी से हिंसा और अराजकता फैल जाती है। यह न केवल सामाजिक ताने-बाने को तोड़ता है, बल्कि राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक स्थिरता पर भी चोट करता है।

राज्य सरकार की यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वह निष्पक्ष और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करे। केवल विपक्ष पर दोषारोपण करके ममता बनर्जी सरकार अपनी ज़िम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकती। यदि बीजेपी राम नवमी के बहाने सांप्रदायिकता का जहर फैला रही है, तो टीएमसी का भी यह कर्तव्य है कि वह केवल मुस्लिम समुदाय की राजनीति करके खुद को धर्मनिरपेक्ष घोषित करने के भ्रम से बाहर आए। दोनों दलों ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी-अपनी रणनीतियों को धर्म और भावनाओं के सहारे गढ़ा है, और यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है।

देश में धार्मिक उत्सव अब आनंद का कारण न होकर भय का पर्याय बनते जा रहे हैं। पुलिस की निष्क्रियता, सरकार की असंवेदनशीलता और राजनीति की क्रूरता ने धार्मिक आयोजनों को सत्ता के लिए एक रणभूमि में बदल दिया है। जब-जब कोई विवादित कानून आता है- चाहे वह नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) हो, वक्फ संशोधन हो या किसी अन्य सामाजिक मुद्दे पर आधारित कानून- उसके विरोध को सांप्रदायिक रंग देना अब राजनीतिक दलों की आदत बन चुकी है।

इसका समाधान केवल कानून व्यवस्था की बहाली से नहीं होगा, बल्कि यह आवश्यक है कि सरकारें अपने प्रशासनिक ढांचे को मज़बूत करें, धार्मिक आयोजनों को नियंत्रित करें, और सबसे महत्वपूर्ण, जनता के बीच विश्वास बहाल करें। यह तभी संभव है जब राजनीति धर्म से ऊपर उठे और जनता की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा पर केंद्रित हो।

वर्तमान में ममता बनर्जी सरकार के लिए यह एक चुनौती भी है और अवसर भी। वह इस स्थिति को एक निर्णायक मोड़ पर लाकर शासन की प्रभावशीलता को पुनः स्थापित कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठना होगा और कानून का समुचित पालन कराना होगा। धर्म के आधार पर कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए, और जो भी कानून तोड़े, उसे कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए चाहे वह किसी भी पार्टी या समुदाय से संबंधित हो।

वहीं बीजेपी को भी यह समझना चाहिए कि सांप्रदायिक उकसावे से तात्कालिक राजनीतिक लाभ तो संभव है, लेकिन दीर्घकालिक परिणाम समाज के लिए विनाशकारी होते हैं। एक सशक्त विपक्ष होने के नाते उसका दायित्व है कि वह संवैधानिक दायरे में रहकर सरकार की जवाबदेही तय करे, न कि धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक युद्ध का औज़ार बनाए।

देश के विभिन्न हिस्सों से मिलती सांप्रदायिक तनाव की खबरें इस बात का संकेत हैं कि राजनीति का धर्मीकरण अब केवल एक राज्य की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुका है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक, यह प्रवृत्ति लगातार फैल रही है, और यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया, तो यह भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर सकता है।

पश्चिम बंगाल के लिए यह वक्त आत्मचिंतन का है न केवल राजनीतिक दलों के लिए, बल्कि प्रशासन, पुलिस और आम जनता के लिए भी। जब तक जनता सांप्रदायिक एजेंडे को नकार कर विकास और सुशासन को प्राथमिकता नहीं देगी, तब तक राजनीतिक दल इस विभाजन को अपनी शक्ति का साधन बनाते रहेंगे।

वक्फ संशोधन और राम नवमी विवादों के बहाने उभरा यह संकट केवल एक सांप्रदायिक झड़प नहीं है, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समरसता की परीक्षा भी है। ममता सरकार के लिए यह एक आख़िरी चेतावनी है कि वह प्रशासनिक जवाबदेही को मज़बूत करे और 'सांप्रदायिक कढ़ाही' में उबलते राज्य को ठंडा करे। अन्यथा, अगला चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक विघटन का कारण बन सकता है। राजनीति को अब आग नहीं बुझानी है, बल्कि आग लगाना बंद करना है।

नया कानून

अवधेश कुमार
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

वक्फ विधेयक पारित होने के मायने

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद वक्फ कानून अस्तित्व में आ गया है तथा सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस तरह अब देश में पुराना वक्फ कानून समाप्त एवं नया कानून लागू हो चुका है। लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों के संपूर्ण बहस को देखें तो विरोध करने वालों ने तथ्यों के आधार पर ऐसे तर्क नहीं दिए जिनसे वाकई साबित हो सके कि वक्फ कानून में बदलाव का यह कदम संविधान विरोधी, इस्लाम विरोधी एवं मुस्लिम विरोधी है तथा इसका उद्देश्य सरकार द्वारा मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा करना है। सरकार के सांसदों द्वारा दिए गए अन्य नेताओं के भाषणों को छोड़ दीजिए तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू द्वारा विधेयक प्रस्तुत करते समय तथा गृह मंत्री अमित शाह के ही वक्तव्य में एक -एक तथ्य संसद की रिकॉर्ड पर रखे गए। संसद में गलत तथ्य रखने के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ सकता है। साफ है कि दोनों नेताओं ने जो कहा वह सच था। विपक्ष के पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए तथ्य थे ही नहीं। विपक्ष के ज्यादातर भाषण राजनीतिक आरोपों के अलावा कुछ नहीं थे। कुछ तो तथ्यों से परे थे। उदाहरण के लिए यह कहना कि वक्फ न्यायाधिकरण के विरुद्ध न्यायालय जाया जा सकता है।

कांग्रेस तथा यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए कानून में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम माना गया और सिविल न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय में मामला रिट के माध्यम से ले जाया गया। हम जानते हैं कि रिट कितना कठिन होता है। जिस संस्था की संपत्तियों को लेकर 40 हजार से ज्यादा विवाद हों और उनमें लगभग 10 हजार मुसलमानों द्वारा लाए गए हों उसके वर्तमान ढांचे को बनाए रखना किसी लोकतांत्रिक, संवैधानिक और प्रगतिशील व्यवस्था का पर्याय नहीं हो सकता। इसमें सुधार की मांग मुसलमानों की ओर से भी की जा रही थी।

इस्लाम में दीन की सेवा के लिए अपनी संपत्तियों को वक्फ करने की अनुमति है। इसे छीना नहीं जा सकता। हालांकि वक्फ नाम इस्लामी नहीं यह अरबी शब्द है। आप किसी तरीके से संपत्ति इस्लाम के तहत दान कर सकते हैं। वक्फ में सरकार ने स्पष्ट किया कि गैर मुसलमानों का हस्तक्षेप नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ में मुतवल्ली और वाकिफ दोनों मुस्लिम समुदाय के होंगे। तो समस्या कहां है? वक्फ बोर्ड की भूमिका इन संपत्तियों के उनके उद्देश्यों के अनुरूप उचित प्रबंधन ,प्रशासन और नियंत्रण तक सीमित है। जो वक्फ बोर्ड संविधान के तहत बना और संसद ने पारित किया वह इस्लाम मजहब का विषय नहीं हो सकता। संसद में पारित सभी कानून उच्चतम न्यायालय के पुनरीक्षण की परिधि में आते हैं। तो इसकी संवैधानिकता का निर्णय उच्चतम न्यायालय में हो जाएगा। संविधान का सामान्य जानकार भी बता सकता है कि इसमें किसी धारा का उल्लंघन नहीं है।

अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ अपने पंथ या मजहब का प्रचार करने, उसके लिए संस्थाएं बनाने आदि के मौलिक अधिकारों की हमारे देश में खासकर मुसलमानों के संदर्भ में दुर्भाग्य से गलत अवधारणा बनी और यही मानसिकता मजबूत हो गई है। इसी कारण ऐसे सारे वैधानिक कदमों को सीधे इस्लाम विरोधी या मुसलमानों के मजहबी मामलों में हस्तक्षेप बता कर दुष्प्रचार किया जाता है और इसका आम मुसलमानों पर असर भी दिखाई देता है। हालांकि धीरे-धीरे इस सोच में भी बदलाव आ रहा है। वक्फ विधेयक पर संसद में बहस के दो दिनों तक हमने देखा कि देश भर में इसके समर्थन में भी प्रदर्शन हुए और अनेक प्रतिष्ठित मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं तथा जमातों के प्रमुखों ने पक्ष में वक्तव्य दिया। उदाहरण के लिए अजमेर शरीफ के प्रमुख हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने कहा कि यदि वक्फ बोर्ड में सुधार किया जाए जिससे मुस्लिम समुदाय को कौशल, शिक्षा और रोजगार के लाभ मिल सके तो यह बहुत जरूरी बदलाव होगा। इस तरह के अनेक बयान हैं जिनसे विरोधी मुस्लिम नेताओं और राजनीतिक दलों के आरोपों का खंडन हो जाता है।

जो सच है ही नहीं उसे प्रचारित करके देश में वोट बैंक की लंबी राजनीति हुई, इसके कारण मुस्लिम समुदाय के अंदर उदारवादी व्यापक सोच वाले हाशिए में गए तथा कट्टरपंथी शक्तिशाली, प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व हावी होते गए। उच्चतम न्यायालय ने 1985 में शाहबानो जैसी एक तलाकशुदा वृद्ध महिला के लिए 138 रुपए मासिक भत्ते की मान्यता दी और ऐसे मुसलमानों द्वारा भ्रम पैदा करने के कारण समुदाय विरोध में उतर गया। वोट बैंक की राजनीति के तहत राजीव गांधी सरकार ने संसद से उसे पलट दिया। उसके बाद से मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, भले उनके नाम पर कानून विरोधी कार्य यहां तक कि भ्रष्टाचार और अपराध भी हो रहे हो उनमें सरकारें दखलअंदाजी बचती ही नहीं रही बल्कि इस व्यवस्था को और सशक्त करने के कानून और ढांचे खड़े कर दिए। एक साथ तीन तलाक की इस्लाम में मान्यता नहीं है। बावजूद मजहबी मामला के नाम पर जारी रहा और सरकारों को पता था, फिर भी महिलाओं के साथ अन्याय तथा पुरुषों द्वारा महिलाओं के शोषण की इस इस्लाम विरोधी व्यवस्था को समाप्त नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने ही इसे किया।

वक्फ की मजहबी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए 1995 में जब कानून में बदलाव हो रहा था तो राज्यसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता सिकंदर वख्त ने कहा था कि वक्फ संपत्तियां गरीब मुसलमानों की सेवाओं,तलाकशुदा महिलाओं और यतीम बच्चों की अमानत है जिसमें खयानत हो रही है। बावजूद विधेयक पारित हुआ और कानून बना। अब मुस्लिम नेता ही प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड के रहनुमा संपत्तियों का अंकेक्षण क्यों नहीं कराते? इससे पता चलेगा कि वक्फ संपत्तियां कहां-कहां और कितनी मात्रा में खर्च हो रही है। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को वक्फ में रजिस्ट्री कर सकता है किंतु सरकारी संपत्ति कैसे वक्फ हो सकती है यह समझ से परे है। सरकार की भूमिका अपने स्तर से गरीबों के कल्याण के लिए काम करना है। दूसरी ओर वक्फ के नाम पर सरकारी, व्यक्तिगत और आदिवासियों की अनुसूचित जमीनों, ऐतिहासिक - पुरातात्विक स्थलों तक पर वक्फ का कब्जा हुआ। सच्चर समिति ने कहा कि इसका प्रबंधन सही तरीके से हो तो 12 हजार करोड़ की सालाना आय हो सकती है जबकि आए केवल 200 करोड रुपए हो रहे हैं। सच्चर आयोग का मूल्यांकन 2005 का था। 2013 के बाद अगर 21 लाख एकड़ जमीन बढ़े हैं तो कल्पना करिए कि 12 हजार करोड़ की संभावित आय का आंकड़ा कितना बढ़ जाएगा। इस समय आय केवल 169 करोड़ है। चूंकि इस्लाम में जकात और वक्फ को मान्यता है इस कारण वक्फ जैसे केंद्रीय कानून की आवश्यकता है। हालांकि भूमि, धर्मस्थल जिनमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, श्मशान घाट, कब्रिस्तान आदि मुद्दे राज्य सरकार के विषय हैं। 1954 में केंद्रीय स्तर पर वक्फ कानून संसद में बना और 1995 तथा 2013 में बदलाव हुए। राज्यों की भूमिका इसमें समाप्त नहीं हुई है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में हिंदू धर्मार्थ कानून है। ये मठों, मंदिरों के प्रशासन संपत्ति और प्रबंधन को नियंत्रित करते हैं। 1955-56 में हिंदू कोड बिल के अनुसार मुसलमान के लिए शादी, तलाक और उत्तराधिकार का कोई कानून नहीं बना। यह प्रगतिशील और न्यायसंगत समाज व्यवस्था के रास्ते की ये बाधायें अब खत्म हो रहीं हैं और धीरे-धीरे मुस्लिम समुदाय के वंचित और हाशिए में पड़े समूह, महिलाओं तथा विवेकशील वर्ग इनका समर्थन कर रहा है।

भारत की संप्रभुता के लिए आवश्यक संशोधन

वक्फ विधेयक

डॉ. भूपेंद्र कुमार

लोकसभा द्वारा पारित वक्फ संपत्ति (संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर काफी चिंता जताई जा रही है। यह विवादास्पद विधेयक 1995 के वक्फ अधिनियम को अपडेट करता है और केंद्र सरकार को वक्फ संपत्तियों पर अधिक नियंत्रण देता है। अगले ही दिन राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी।

वक्फ का अर्थ है चल या अचल संपत्ति को इस्लाम के नाम पर समर्पित करना, जिसका ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनमें मस्जिदें, मदरसे, शेल्टर होम और मुसलमानों द्वारा दान दी गई हजारों एकड़ जमीन शामिल हैं। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है, हालांकि कई संपत्तियाँ अतिक्रमण जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारदर्शिता, जवाबदेही, आधुनिकीकरण और दक्षता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। इसमें गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और वित्तीय सुधारों का प्रावधान है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य अतिक्रमण को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों का उपयोग समुदाय के कल्याण के लिए हो।

संशोधन वक्फ न्यायाधिकरण को काफी लचीलापन देता है क्योंकि इसमें देरी के लिए 'पर्याप्त कारण' को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। यह विस्तार की अधिकतम समय सीमा भी तय करता है और अनुरोध की प्रक्रिया को रेखांकित करता है।

शासन कर रही एनडीए गठबंधन ने इस विधेयक का जोरदार समर्थन किया है और इसे अल्पसंख्यकों के लिए फायदेमंद बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, 'संसद द्वारा पारित यह कानून पारदर्शिता बढ़ाएगा और लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा।'

सरकार का कहना है कि 1995 के कानून में वक्फ संपत्तियों के विनियमन, शीर्षक विवादों और अवैध कब्जों को लेकर कुछ खामियां हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, 'अगर सरकार यह विधेयक नहीं लाती, तो संसद भवन और हवाईअड्डे तक को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा किया जा सकता था। यह संदर्भ समझने में मदद करता है कि संशोधन किन विशिष्ट समस्याओं को संबोधित करना चाहता है।'

विपक्ष ने संसद में 12 घंटे चली बहस के दौरान इसे मुस्लिम विरोधी कदम बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि निचले सदन में 288 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में और 232 ने विरोध में मतदान किया। मोदी ने कहा, 'इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभिन्न दलों के विरोध के बावजूद यह विधेयक मनमाने तरीके से लाया गया।'

यह विविधता इस मुद्दे की जटिलता और महत्व को दर्शाती है। कांग्रेस सदस्य इमरान मसूद ने सरकार से पूछा कि वह 'प्रैक्टिसिंग मुस्लिम' की कैसे परिभाषा करेगी। उन्होंने सवाल किया, 'आपकी परिभाषा क्या होगी? सभी मुसलमान पांचों वक्त नमाज़ नहीं पढ़ते और न ही सभी रोज़ा रखते हैं। तो फिर मापदंड क्या होगा?'

मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वक्फ विधेयक वक्फ कानूनों को कमजोर करने के लिए लाया गया है। उनका मानना है कि यह कानून अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा और धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29) को कमजोर करेगा। उन्होंने सरकार के बढ़ते नियंत्रण और व्यापक परामर्श की कमी पर भी आपत्ति जताई। यह चिंताएं विधेयक के संभावित नकारात्मक प्रभाव और और अधिक चर्चा व परामर्श की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों का मानना है कि यह सरकार को बहुत अधिक शक्ति देता है और वर्तमान कानून में कई बदलावों का सुझाव देते हैं। लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि यह विधेयक 'संविधान को कमजोर करेगा, अल्पसंख्यक समुदायों को बदनाम करेगा, भारतीय समाज को विभाजित करेगा और अल्पसंख्यकों को अधिकारहीन बना देगा।'

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष अल्पसंख्यकों को डरा रहा है और 'यह भ्रम पैदा कर रहा है कि यह विधेयक मुस्लिम भाइयों की धार्मिक गतिविधियों और उनकी दान की गई संपत्ति में हस्तक्षेप करेगा।' सरकार का दावा है कि विधेयक वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अधिक पारदर्शी बनाएगा।

यह विधेयक पहली बार पिछले अगस्त में संसद में पेश किया गया था। कड़े विरोध के कारण इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने समिति द्वारा सुझाए गए 25 संशोधनों के साथ एक संशोधित संस्करण प्रस्तुत किया। जेपीसी में विपक्ष और सत्तारूढ़ दल दोनों के सदस्य शामिल थे।

समर्थकों का कहना है कि वक्फ बोर्ड भारत के सबसे बड़े ज़मीन मालिकों में से हैं। वक्फ संपत्तियां 9,40,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हैं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

जवाहर चौधरी

राजा डरता है कला से

मंत्री ने कहा कि 'अपने राज्य में यह एक बड़े कलाकार हैं चित्र बनाते हैं.....' राजा ने प्रश्न किया -'चित्र क्यों बनाते हैं!? क्या होता है चित्र बनाने से? अगर कल युद्ध हुआ तो हमारे सिपाही क्या चित्र लेकर मैदान में उतरेंगे!! तुम हथियार बनाओ। राज्य अंदरूनी और बाहरी खतरों से घिरा हुआ है, हमें हथियारों की जरूरत है। तुम जानते हो अच्छा हथियार बनाने और चलने वाला सबसे बड़ा कलाकार और देशभक्त होता है।'

महाराज की कीर्ति चांद सितारों तक पहुंचे मलिक। किंतु निवेदन करता हूं कि मुझे हथियार बनाना नहीं आता है। मैं चित्रों की प्रदर्शनी लग रहा हूं । आप उद्घाटन कर देते और एक नजर डाल लेते तो कला का सम्मान बढ़ जाता। 'चित्रकार ने विनम्रता से हाथ जोड़ दिए।

हथियार नहीं बना सकते तो गाना तो गा सकते हो। गाना तो कला है कोई भी कर सकता है। चलो गाओ जरा और दरबार का मनोरंजन करो।'

गाने वाले कलाकार दूसरे होते हैं महाराज।

'सच्चे कलाकार को सब आना चाहिए। इसमें पहला दूसरा तीसरा कलाकार क्या होता है!'

मामला बिगड़ता देख मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। 'महाराज यह राज्य का श्रेष्ठ चित्रकार है इसके प्रशंसक भी बहुत है यदि आप प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन कर लेंगे तो कला के लिए यह अच्छी बात होगी।'

लेकिन इसके चित्रों से राज्य को क्या लाभ होगा।

'राजन इसके चित्र देखकर प्रजा के मन में प्रसन्नता होगी।'

ठीक है पर प्रजा की प्रसन्नता से राज्य को क्या लाभ होगा?

'महाराज अगले माह आपके लिए राज-कीर्ति पंचकोटि यज्ञ होना है। यदि प्रजा प्रसन्न हुई तो हम उससे यज्ञ कर वसूल सकेंगे। प्रसन्न प्रजा घी और हवन सामग्री का ढेर लगा देगी। इसलिए हे राजन, चित्रकार को सहयोग करने की कृपा करें।'

'महामंत्री, यदि इसके चित्र देखकर लोग प्रसन्न नहीं हुए, कर और हवन सामग्री नहीं दी तो इससे भरपाई कैसे की जा सकेगी?' महाराज ने सोच कर प्रश्न रखा।

'चित्रकार तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है?'

'संपत्ति नहीं है भगवान । किराए के घर में रहता हूं, रुखा सूखा खाता हूं। लेकिन मुझे विश्वास है कि महाराज पधारेंगे तो प्रजा अवश्य प्रसन्न होगी।' चित्रकार ने निवेदन किया।

'राज कीर्ति यज्ञ की सफलता के लिए आपको चलना चाहिए महाराज। करों के बोझ से दबी प्रजा से एक और कर लेने के लिए चित्रकला प्रदर्शनी दिखाने का प्रयोग बुरा नहीं है। ' मंत्री ने समझाया।

महाराज राजी हो गए और तय स्थान पर अपने मंत्रियों के साथ पहुंचे।

'यह क्या! ज लाल रिबन!! ... लाल हटा दो हरी रिबन लओ और इसे हम कैंची से नहीं तलवार से काटेंगे। '

तुरंत व्यवस्था की गई और उद्घाटन हो गया। अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी थी। महाराज एक पेंटिंग के सामने खड़े हो गए और चित्रकार से पूछा - यह क्या है?

'यह सूर्योदय का दृश्य है महाराज फूल खिले हैं चिड़िया चहक रही है उमंग उत्साह का वातावरण दिखाया है।'

'लेकिन सूर्य लाल है! उसके प्रकाश से आकाश लाल है! फूल भी लाल खिल रहे हैं! चिड़ियों की चोंच भी लाल है!! एक एक पेंटिंग में इतना इतना लाल!! ... कम्युनिस्ट हो क्या?!'

महाराज नाराज लगे।

'नहीं महाराज ।' चित्रकार ने हाथ जोड़ दिए।

'प्रजा को क्या संदेश जाएगा इससे!! महामंत्री, आप तो कह रहे थे कि लोग कर देंगे। मुझे तो लगता है इसे देखकर बगावत कर देंगे।'

'महाराज, कम्युनिस्ट अब हैं कहां!! जो बचे हैं वे बीपी और कोलेस्ट्रॉल की गोलियां खाते पड़े हैं कहीं। उनके सारे लाल झंडों को प्रजा ने धर्मग्रंथो को बाँधने के काम में ले लिया है। आप चिंता ना करें राजन, अब लाल से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है।' मंत्री ने समझाया।

'अरे महामंत्री! चित्रकार की दाढ़ी देखो ! खद्दर के कपड़े देखो !पांव में जूतियां भी नहीं है !यह जरूर कामरेड है। हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते हैं। सारे चित्र जप्त करें और चित्रकार को मरने के लिए जंगली जानवरों के सामने छोड़ दें।' कह कर वो चले गए।

चित्रकार समझता रहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। भाग्य से मंत्री को दया आ गई। जान बचाने के लिए उसने चित्रकार को राज्य से बाहर कहीं भगा दिया।

अनुभव

राग तेलंग

लेखक स्तंभकार हैं।

ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी: अंततः एलआईसी

यह तो आप जानते ही हैं कि पीएसयू यानी सार्वजनिक उपक्रम हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में अतुलनीय योगदान देते हैं। पहला तो राजस्व के रूप में,दूसरा विराट सामूहिक श्रमशक्ति के उत्पादक होने की उपलब्धि के रूप में। और यह भी एक तथ्य है कि पीएसयू की सफलता देश की कार्य संस्कृति की गुणवत्ता का भी परिचायक होती है।

इसी क्रम में कहना है कि एलआईसी भारत का सबसे बड़ा पीएसयू है और हमारे आसपास के लगभग हर चौथे-पांचवें व्यक्ति की डिक्शनरी में बीमा पालिसी नाम का जो शब्द दर्ज है उसका ओरिजिन एलआईसी ही है। यह हम सभी की उत्सुकता का विषय है कि आखिर ऐसा कौन-सा एलिमेंट (फिलामेंट) है जो आज भी विशालकाय संरचना वाले इस पीएसयू को सामयिक यानी कन्टेंम्परेरी बनाए हुए है। यह भी हैरान करने वाली बात है कि एलआईसी में जरूर ही ऐसी कोई खासियत है जो बाजार में गिरावट या कहें एक्सटिंक्शन के दौर में भी उसे विश्वसनीय बनाए हुए है। मैंने जीवन में विभिन्न प्रकार की सर्विस की हैं और सबसे लंबा समय एक पीएसयू की सेवा में रत रहा। इस तरह एक पीएसयू का अच्छा और सबसे बुरा दौर भी मेरे देखने में आया। यही कारण है कि किसी भी संस्थान की सेहत से जुड़े मानवीय पहलुओं और उनके असर का विश्लेषण मेरी दृष्टि में आ ही जाता है।

बहुधा हमें लगता है कि सुरक्षा का इंस्टिंक्ट सिर्फ इंडीविजुअल प्राणियों का ही नेचुरल वैशिष्ट्य है और यह सामाजिक उद्देश्यों के लिए समर्पित मनुष्य निर्मित संस्थानों या नेटवर्क में नहीं पिरोया जा सकता। आज हंसध्वनि में हम इसी गुण-विशेष के इर्द-गिर्द अपनी बातचीत केंद्रित रखेंगे।

लेकिन पहले बात कुछ अलग तरह की और दिलचस्पी जगाने वाली जानकारियों की। प्रकृति में मधुमक्खियों और चींटियों की जीवनशैली कालोनी मॉडल आधारित होती है। अर्थात उनके कार्यकलाप सामूहिकता आधारित होते हैं। कड़े परिश्रम के प्रतीक ये जीव जीवन में बूंद-बूंद बचत की महत्ता और संकटकाल में सामूहिकता,एकजुटता की भावना के सटीक उदाहरण हैं,और सामूहिक प्रयासों से मिठास कैसे पैदा की जाती है इस मधुर ख़्याल के परिचायक भी। चींटियों में और मधुमक्खियों में कम्युनिकेशन नायाब तरीके घटता है। चींटियां एक तरह की हार्मोन जैसी सुगंध प्रणाली यानी फेरोमोन्स के जरिए और मधुमक्खियां अपने डांसिंग पैटर्न के जरिए आपसी संवाद करती हैं। इसे हम इंस्टिंक्ट बेस्ड कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं यानी बाय डिफॉल्ट,अंतर्निहित भाषा संवाद प्रणाली।

आप सोच रहे होंगे कि संवाद की इस विशेष प्रणाली का उल्लेख आखिर भला यहां क्यों!

ठीक है! थोड़ा रूकिए,आगे जब हम जीव के स्व-संरक्षण संबंधी अंतर्निहित सिस्टम्स की बात करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर भी मिल ही जाएगा।

तो हमने अभी समूह आधारित जीवन प्रणाली के जीवन संरक्षण से जुड़े बेसिक इंस्टिंक्ट के पहलू को देखा और पाया कि समूह स्वतः ही अपने समूह के लिए आहार की व्यवस्था करता है और संकट के समय समूह ही सामूहिक होकर अपनी सुरक्षा करता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में समूह में आपसी संवाद और उससे उनमें बनी समझ की प्रणाली का बहुत ही महत्व है। यहां यह जो बात कही जा रही है वह स्व-संरक्षण या सरवाइवल के बारे में है।

विगत समय में मुझे एलआईसी की कार्यप्रणाली में गुंफित एक ऐसे एलिमेंट का अनुभव हुआ जिससे पता चलता है कि वृहदाकार संस्थान भी विशिष्ट व दुर्लभ अवसरों पर सरवाइवल इंस्टिंक्ट से काम लेते हैं और उसका नतीजा उनके हितों व उद्देश्यों के अनुरूप ही होता है। जाहिर है ऐसे संस्थानों के प्रबंधकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह दूरगामी दृष्टि निहित होती है।

कम्प्यूटर तकनीक के आ जाने से बड़े कामों का संचालन व संयोजन आसान तो हुआ ही है साथ ही इस तकनीक ने मानव जीवन में उपयोगिता कुछ इस तरह सिद्ध कर दी है कि आमजन कम्प्यूटर की भौतिक संसार द्वारा प्रदत्त बुद्धि को मनुष्य को ईश्वर प्रदत्त बुद्धि से भी श्रेष्ठ मान बैठा है। इसी मनोग्रंथि के उकसावे के फलस्वरूप वह आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का आतंक की हद तक का जुनूनी समर्थक बन बैठा है। कहने की बात नहीं कि ऐसा मान भर लेने से हम तकनीकी और तकनीक विकसित करने वाले मालिकों की गुलामी स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा बनाई और पढ़ाई गई अंग्रेजी मानसिकता की शिक्षा की दासता भी स्वतः प्रकट कर देते हैं। यह सनातन वाक्य है कि कृत्रिम कभी भी नैसर्गिक यानी ओरिजनल की जगह नहीं ले सकता। मानव के कौशल,हुनर आधारित बुद्धि से तैयार वस्तु में जो सुगंध है वह बेजान कम्प्यूटर से तैयार माल,हां! माल में कहां नसीब होगा।

यह समझने वाली बात है कि उपभोग की जीवनशैली के आदी लोगों व बाजारवादी ताकतों ने ही यह भ्रम फैलाया है कि कम्प्यूटर बुद्धि मानव बुद्धि से श्रेष्ठ है और ऐसा इसलिए ताकि इस धारणा के पुष्ट होने से विश्व में पश्चिम की तकनीक की बिक्री का बाजार सदाबहार बना रहे।

बहरहाल इस बात को यहीं छोड़ते हैं और आते हैं एक ऐसे विरल अवसर की बात पर जहां कम्प्यूटर बुद्धि और मानव बुद्धि एक-दूसरे के समानांतर आ खड़े होते हैं।

जो कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग के जानकार हैं वे इस तथ्य को समझते होंगे कि मानव जीवन की सारी घटनाएं प्रेडिक्टेबल नहीं हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि सब कुछ को डाटा में इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता। बल्कि सीधी सी बात यह है कि मृत्युबोध होने से मानव जीवन की परिस्थितियां बेहद डायनामिक और अनिश्चित प्रकार की हैं जिनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसीलिए एआई और ऑर्गेनिक इंटेलीजेंस के बीच तुलना निरर्थक है, बेमानी है। एआई के मनुष्य जीवन पर वर्चस्व की एकतरफा कल्पना को महिमामंडित करना प्राकृतिक मनुष्य में ऑर्गेनिक डर पैदा कर इस पृथ्वी तंत्र पर नियंत्रण के खतरनाक कोणों की ओर संकेत है।

कोरोना काल ऐसा ही दौर था जिसकी प्रतीति किसी को भी न थी,एआई,कम्प्यूटर को भी नहीं। जीवन में इस दौर से सबक मिला कि कोई भी अनपेक्षित ड्रैगन आपके सिस्टम में कभी भी एन्ट्री ले सकता है,फिर वह चाहे शरीर के अंदर पेट में हो या दिमाग में या खुले वातावरण मे?। सो हर हाल में वज्रपात के लिए पहले से तैयारी बहुत ज़रूरी है। इसी दौर में एलआईसी की मेरी एक पॉलिसी भी समयबाधित हो गई थी। वाकया कुछ ऐसा रहा कि इस पालिसी के नवीकरण यानी रिनुअल प्रोसेस के मुद्दे पर लास्ट डेट से संबद्ध एक अनडिकोडेबल परिस्थिति विशेष निर्मित हो गई। जिसके कारण मनुष्य मेधा और डाटा बेस्ड लैंग्वेज की सीमित मेधा वाले कम्प्यूटर का असमंजस के दोराहे पर आमना-सामना हो गया। फलतः कुछ कालखंड के लिए पालिसी रिनुअल प्रक्रिया में अनिर्णय जैसी बाधक स्थिति बन आई। याद करता हूं कि बीएसएनएल में रहते हुए जैसे दो अंको के वर्ष निन्यानवे को चार अंकों के वर्ष दो हजार का कमांड कम्प्यूटर को समझाने में वाय टू के नेशनल प्रोजेक्ट (इकतीस दिसंबर वर्ष उन्नीस सौ निन्यान्वे की रात्रि) में सहभागी होकर अनुभव लिया था कुछ-कुछ वैसा ही अनुभव मेरी इस पालिसी के संदर्भ में सभी संबंधितों को हुआ। अब आगे और विस्तार में न जाते हुए परिणामी तथ्य पर आते हैं।

कुछ बीस-पच्चीस दिनों के झंझावात काल में ऊहापोह के बीच हुआ यह कि अंततः तकनीक पर मानव बुद्धिबल के कौशल की श्रेष्ठता बहाल हुई और वह समयबाधित जीवन बीमा पालिसी पुनः चालू हुई। इस असमजंस भरे कालखंड में एलआईसी की ज़ोनल मैनेजर यानी प्रादेशिक प्रबंधक श्रीमती केरकट्टा व उनकी टीम ने अपनी कुशल संयोजन क्षमता से व बड़े ही आश्वस्त भाव से मामले को सुलझाया। परिस्थितिनुसार धैर्य व संयम के साथ निरपेक्ष दृष्टि अपनाकर किसी भी जटिल से जटिल समस्या का निवारण किया जा सकता है ऐसा मैंने एलआईसी के विभिन्न आदर्श प्रबंधकों के स्मित चेहरों पर इस टास्क के दौरान व उसकी समाप्ति के अवसर पर देखा। यानी जब मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करने गया,तब। यह अनुभव एलआईसी की दक्षता और विश्वसनीयता का ऑन द रिकॉर्ड मेमॉयर है।

बहुत पुरानी सभ्यता होने के नाते हम भारतीय कम से कम पांच हज़ार वर्षों के मानवीय सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये अक्षुण्ण मूल्य बिना जीवन प्रबंधन दृष्टि के नहीं पनपे होंगे इस बोध से किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ यह कि सभ्यता व समाज संचालन के लिए आवश्यक प्रबंधन कौशल हमारे अस्तित्व जितना ही पुराना और शुद्ध है। मैनेजमेंट या प्रबंधन पूर्व का पुराना विज्ञान रहा है जिसे आज का पश्चिम जगत मैनेजमेंट टेक्नीक कहता है। यह ध्यान रहे कि मानवीय व्यावहारिकता में विज्ञान शब्द पवित्रता के भाव को प्रतिबिंबित करता है और वहीं दूसरी ओर तकनीक शब्द का आज हाल यह है कि वह चालाक या स्मार्ट कहे जाने में ही उसकी स्वीकार्यता है। आज के समय में मैनेजमेंट का प्रयोग,जिस तरह तकनीक की आड़ लेकर कड़े श्रम से अर्जित हमारी जमापूंजी पर कुदृष्टि डालते हुए,ठगी व लूट को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है,वह किसी से छुपा नहीं है। नित घटित होते फिजिकल और साइबर अपराधों को इस कोण से देखें तो पश्चिमी संस्कृति की फोटोकापी होकर यह मैनेजमेंट नामक विषय जीवन में चालाकी और धूर्तता घोलने की टेक्नालॉजी भर बनकर रह गया है। जनोपयोगी टेकनालॉजी की इस मैली छवि को भारतीयता के एसेंस से धो-पोंछकर योजनाकार्य-तंत्र नियोजन मंत्र के पाठ पढ़ाकर भूले-भटकों का शुद्धीकरण किया जा सकता है।

मैं यह सब इतने विश्वास के साथ क्यों कह रहा हूं क्योंकि इस तथ्य के ठोस प्रमाण हैं कि प्रबंधन हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट में है और वह हमारी संस्कृति की जड़ों के रेशे-रेशे में जन्म से ही समाया हुआ है। आइए यहां उपनिषद से लिया गया एक सूत्र समझते हैं जिसमें कहा गया है कि कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिससे कोई मंत्र प्रारंभ होता न हो,और कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जिससे कोई औषधि बनती न हो,और कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से अयोग्य हो,और ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे मनुष्यों से काम लेने वाले ही दुर्लभ हैं।

अमंत्रं अक्षरं नास्ति,नास्ति मूलं अनौषध?।
अयोग्यः पुरूषः नास्ति,योजकः तत्र दुर्लभः।।

आपने नोट किया यहां योजक शब्द का आशय प्रबंधक यानी काम लेने वाले मैनेजर से है। है न! दिलचस्प किस्सा यह मैनेजमेंट का।

इस आलेख को लिख लेने के बाद एक दिन मैंने प्रदेश एलआईसी के ज़ोनल ऑफिस के बाहर खड़े रहकर हमारे भारत की शान एलआईसी परिवार के अभिनंदन स्वरूप उसके प्रतीक चिन्ह और उसके नीचे लिखी स्क्रिप्ट 'योगक्षेमं वहाम्यहम' की ओर विनत भाव से देखा।

'योगक्षेमं वहाम्यहम्' यह भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का ध्येय वाक्य है. यह श्लोक भगवद्गीता के नौवें अध्याय के 22 वें श्लोक से लिया गया है।

प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने योगक्षेम की अवधारणा की बात की है। इसे अच्छे शासन या राज धर्म का आधार बताया गया है। 'योगक्षेम' का मतलब है,कल्याण,खुशी, स्वास्थ्य या किसी व्यक्ति या समुदाय की समृद्धि।

योगक्षेमं वहाम्यहम् वाक्य का अर्थ है,'मैं आपकी कुशलता (योग) और सुरक्षा (क्षेम) का भार उठाता हूं'। अतिरिक्त व्याख्या यह भी है कि जो आपके पास है, उसकी रक्षा करूंगा और जो नहीं है,वह आपको दिलवाऊंगा।

सोचता हूं राष्ट्र को समर्पित एक संगठन का ध्येय वाक्य कितना सार्थक है इस दर्ज अनुभव के संदर्भ में और वे लोग ऋषितुल्य ही होंगे जिन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम को यह फलित मंत्र दिया होगा।

भारत वर्ष की आर्थिक अधोसंरचना के आधार स्तंभ एलआईसी को कर्मठता और प्रतिबद्धता के साथ जारी यशस्वी यात्रा के लिए शुभकामनाएं।

दृष्टिकोण

अनिल ठाकुर

लेखक स्तंभकार हैं।

विधायिका और न्यायपालिका के दायरे पर सवाल

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार एवं राज्यपाल के बीच विधेयकों को रोके जाने एवं राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए लंबित विधेयकों को लेकर चल रहे विवाद पर एक ऐसा फैसला दिया जो चौंकाने वाला है। न्यायालय ने राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजे गए विधेयकों पर तीन महीने में निर्णय लेने के निर्देश जारी करते हुए विधेयकों को मंजूरी दे दी। ये मामला फैसले से ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्र का है।

हमारे देश का एक लिखित संविधान है, लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुनी जाती है एवं एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। संविधान में विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका की शक्तियों, अधिकारों को बहुत ही तुलनात्मक तरीके से संतुलित किया गया है । इनमें से किसी को भी एक दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, और ना ही अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने की ताकत दी गई। दूसरे शब्दों में कहे तो चेक और बैलेंस पद्धति अपनाई गई है।

इस मामले पर चर्चा करने से पहले भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने सांसदों के अयोग्यता के मामले में उन्हें उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश पर जो कहा था ,उस पर गौर करना जरूरी है । उन्होंने कहा था 'अदालत के पूरे सम्मान के साथ मैं महसूस करता हूँ कि सबसे पहले अदालत यह फ़ैसला करती कि उसके पास इस मामले की सुनवाई का संवैधानिक अधिकार है या नही। उनका कहना था,' जब तक इस बात का फ़ैसला नहीं हो जाता, तब तक सांसद को बर्ख़ास्त करने का अधिकार है या नहीं, इसके लिए स्पीकर को नोटिस देने की ज़रूरत नहीं थी'।

एक अन्य कार्यक्रम में उन्होंने उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों में उच्चतम न्यायालय के प्रयासों की निंदा करते हुए कहा था कि कार्यपालिका को न्यायपालिका के साथ टकराव से बचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतें बुद्धि और शक्ति का दुरुपयोग कर रही हैं। सोमनाथ चटर्जी ने उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों में 'सभी शक्तियों को हथियाने' के उच्चतम न्यायालय के प्रयासों की भी निंदा की थी । उन्होंने यह चेतावनी भी दी थी कि कार्यपालिका को न्यायपालिका के साथ 'चल रहे झगड़े' से बचना चाहिए और चीजों को सही करने के प्रयास जारी रखने चाहिए । उनका मानना था कि अदालतों ने अपनी बुद्धि और शक्ति का दुरुपयोग किया है।

उपरोक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए हमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार करना चाहिए। यह मान भी लिया जाए कि राज्यपाल की मंशा संदेहास्पद थी । लेकिन क्या उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति की मंशा पर भी संदेह है ? क्या उच्चतम न्यायालय का विधेयकों को मंजूरी एवं राष्ट्रपति को निर्देश एक संवैधानिक पद की गरिमा को चुनौती नहीं है ? इस विषय पर अटॉर्नी जनरल ने गंभीरता से यह कह कर कि राष्ट्रपति के पक्ष को भी सुना जाना चाहिए था, न्यायपालिका को नसीहत दे दी ।

यह इसलिए भी विचारणीय है क्योंकि ऐसे कई कानून/नियम है, जहां राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है। उदाहरणार्थ मृत्यु दंड में दया की याचिका में राष्ट्रपति महोदय के लिए कोई समय सीमा नहीं है। उल्लेखनीय है कि आतंकवादी याकूब मेमन की दया की याचिका लंबे समय तक राष्ट्रपति के पास लंबित रही थी। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में उच्चतम न्यायालय किसी अपराधी को निर्णय में देरी के आधार पर मृत्युदंड के बदले आजीवन कारावास या बरी भी कर दे तो आश्चर्य नहीं होगा ।

बेहतर होता उच्चतम न्यायालय इन विधेयकों को तुरंत मंजूरी देने एवं भविष्य में तीन महीने अवधि में निर्णय लेने की अनुशंसा करते हुए राष्ट्रपति के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करता। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र विधानसभा के विधायकों की अयोग्यता के मामले में उच्चतम न्यायालय ने विधान सभा अध्यक्ष को एक निश्चित तिथि तक निर्णय लेने का निर्देश दिया था। फिलहाल इस फैसले के संदर्भ में राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका, केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकार पर संक्षेप में बात करने के पहले यह याद रखा जाना जरूरी है कि केंद्र सरकार अपने प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति करती है, इसी प्रकार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही संवैधानिक निर्णय लेता है। यही दो मुख्य कारण है जो विवाद की जड़ है। राज्यपालों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह पहली बार नहीं उठे है। चुनी हुई सरकारों की बर्खास्तगी, सदन के बाहर बहुमत का फैसला, विधेयकों के अनुमोदन में देरी, प्रशासनिक अधिकारियों को सीधे निर्देश जैसे अनेक उदाहरण है जिन्हें लेकर राज्यपाल की भूमिका उचित नहीं मानी गई। पहली बार कर्नाटक में बोम्मई सरकार की बर्खास्तगी को न्यायालय में चुनौती देने एवं पुनः बहाली के बाद राज्यपाल की भूमिका चर्चा में आई। उस समय भी बोम्मई सरकार की बर्खास्तगी एवं राष्ट्रपति शासन के आदेश को लेकर राष्ट्रपति की भूमिका पर सवाल उठे थे, लेकिन न्यायलय ने इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की थी।

यह दोहराना शोभा नहीं देता लेकिन जस्टिस वर्मा के निवास परिसर में पाए गए अधजले नोटो से न्यायपालिका की साख को जो ठेस पहुंची है, उसमें इस तरह के निर्णयों से बढ़ोतरी ही होगी। जजों द्वारा फैसलों के अतिरिक्त की गई टिप्पणियों से भी विवाद हुए है। कई वरिष्ठ न्यायधीशों को महाभियोग का सामना करना पड़ा है, जिसने न्यायपालिका की छवि को धूमिल किया है। यह कह कर बचा नहीं जा सकता है कि अभी तक कोई महाभियोग साबित नहीं हुआ है। निवृतमान न्यायधीशों के सरकार द्वारा किसी पद या राज्यसभा में मनोनयन को लेकर उनके सेवाकाल में निष्पक्ष होने के संदेह को जन्म दिया है। क्या उच्चतम न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर यह आदेश पारित करेगा कि भविष्य में कोई भी न्यायधीश अपनी सेवानिवृति के बाद पांच वर्षों तक मनोनीत लाभ का पद नहीं लेगा ? कठघरे में सभी है, मगर जरूरत है खुद को कठघरे में रखकर आत्मावलोकन की।

शिक्षा

प्रियंका सौरभ

लेखक स्तंभकार हैं।

सरकारी स्कूलों को बंद करने की बजाय उनका रुतबा बढ़ाएं

भारत जैसे लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय की परिकल्पना वाले देश में सरकारी स्कूल केवल शिक्षा के केंद्र नहीं, बल्कि समान अवसर की उम्मीद भी होते हैं। ये वे स्थान हैं जहाँ समाज का सबसे कमजोर तबका, सबसे कमज़ोर बच्चा भी सपना देख सकता है-आगे बढ़ने का, कुछ बनने का। पर दुर्भाग्यवश आज सरकारें इन्हें बोझ मानने लगी हैं। कहीं स्कूलों का विलय हो रहा है, कहीं उन्हें निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। सवाल यह है कि जब देश की रीढ़ मजबूत करनी हो, तो उसे काटा क्यों जा रहा है?

सरकारी स्कूल: व्यवस्था की रीढ़

भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है, पर अधिकार सिर्फ कागज़ पर नहीं, ज़मीनी हकीकत पर टिकते हैं। सरकारी स्कूल गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय बच्चों के लिए एकमात्र विकल्प हैं। निजी स्कूलों की ऊँची फीस, प्रवेश प्रक्रिया और बाज़ारी सोच उन्हें आम आदमी की पहुँच से बाहर कर देती है। ऐसे में सरकारी स्कूल न केवल शिक्षा देते हैं, बल्कि सामाजिक समरसता और बराबरी की भावना भी गढ़ते हैं।

क्यों गिरा सरकारी स्कूलों का रुतबा?

सरकारी स्कूलों की छवि को योजनाबद्ध तरीके से खराब किया गया। दशकों तक उन्हें बजट की मार झेलनी पड़ी। शिक्षकों की भारी कमी, ढांचागत बदहाली, पढ़ाई में रुचि की कमी और प्रशासनिक उपेक्षा ने सरकारी स्कूलों को रसातल की ओर धकेला। दूसरी ओर, निजी स्कूलों को लगातार बढ़ावा दिया गया-टैक्स में छूट, जमीन में रियायतें, नियमों में नरमी। सरकारी स्कूल के बच्चे को 'कमतर' और प्राइवेट स्कूल के बच्चे को 'सक्षम' मानना एक मानसिक रोग बन गया।

बंद करने की नीति: हरियाणा का उदाहरण

हरियाणा में सरकारी स्कूलों को बंद करने की नीतिगत प्रक्रिया इसका जीवंत उदाहरण है। वर्ष 2022 में राज्य में कुल 292 सरकारी स्कूलों को बंद या एकीकृत किया गया, जिनमें से अधिकांश में छात्रों की संख्या 25 से कम या शून्य थी। यह आँकड़ा राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और यह रुकने वाला नहीं है।

जनवरी 2024 में सरकार ने घोषणा की कि वह उन 800 प्राथमिक स्कूलों को बंद करने की योजना बना रही है जहाँ छात्रों की संख्या 20 से कम है। इनमें पढ़ने वाले लगभग 7,349 बच्चों को अन्य निकटवर्ती स्कूलों में भेजा जाएगा, और परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। सवाल यह है कि यह समाधान है या सिरदर्द को सिर हटाकर खत्म करने वाली सोच?

समाधान: बंद नहीं, बदलाव

अगर सरकारी स्कूलों में समस्या है, तो उन्हें बेहतर बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। निम्नलिखित कदम इस दिशा में निर्णायक हो सकते हैं। 1. शिक्षकों की नियमित और पारदर्शी भर्ती शिक्षकों की कमी सबसे बड़ी बाधा है। योग्य और प्रेरित शिक्षक ही किसी भी स्कूल की नींव होते हैं। 2. बुनियादी ढांचे में निवेशः साफ-सुथरी इमारत, शौचालय, पीने का पानी, लाइब्रेरी और डिजिटल सुविधाएं–ये बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करते हैं। 3. स्थानीय समुदाय की भागीदारी- स्कूल प्रबंधन समितियों को मज़बूत बनाकर स्थानीय लोगों को फैसलों में शामिल किया जाए। 4. गुणवत्ता की निगरानी और मूल्यांकनः सिर्फ नामांकन नहीं, शिक्षण की गुणवत्ता पर भी नज़र रखी जाए। 5. मीडिया में सकारात्मक छवि निर्माणः सरकारी स्कूलों की सफलता की कहानियाँ सामने लाई जाएं ताकि उनकी साख बहाल हो।

दिल्ली मॉडल: एक प्रेरणा

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरकारी स्कूलों के कायाकल्प की दिशा में उदाहरण पेश किया है। न केवल नई इमारतें बनीं, बल्कि शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई, स्कूलों को साफ-सुथरा और तकनीक से लैस बनाया गया, और सबसे बड़ी बात-सरकार के मंत्री खुद स्कूलों में जाकर निरीक्षण करने लगे। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में रिज़ल्ट भी बेहतर हैं और आत्मविश्वास भी।

शिक्षा को बाज़ार नहीं, अधिकार समझिए

शिक्षा को व्यापार बना देने से एक वर्ग आगे तो बढ़ेगा, पर बहुसंख्यक वर्ग पीछे ही रह जाएगा। इससे सामाजिक विषमता और गहरी होगी। सरकार की भूमिका तटस्थ नहीं, सक्रिय होनी चाहिए। उसे चाहिए कि वह शिक्षा को एक सामाजिक दायित्व माने, न कि राजस्व की वस्तु।

सरकारी स्कूलों की साख बहाल करना, लोकतंत्र की साख बहाल करना है

अगर सरकारी स्कूल बंद होते हैं, तो यह केवल शिक्षण संस्थानों का बंद होना नहीं है, यह उस विचार का पतन है जिसमें हर बच्चे को समान अवसर मिलने चाहिए थे। यह संविधान में आस्था को डगमगाने जैसा है। यह लोकतंत्र की आत्मा पर आघात है।

स्कूल मत बंद करो, सोच बदलो

सरकारी स्कूलों को बंद करना आसान है, लेकिन एक पूरी पीढ़ी का भविष्य बंद हो जाएगा। यह वक्त है सोच बदलने का, दिशा बदलने का। हमें चाहिए कि सरकारी स्कूलों को गर्व का केंद्र बनाएं–ऐसे संस्थान जहाँ शिक्षा का अधिकार नहीं, सम्मान मिले। जहाँ बच्चा न ये पूछे कि वो प्राइवेट स्कूल से है या सरकारी से, बल्कि ये पूछे कि वो सीख क्या रहा है, सोच क्या रहा है, और आगे क्या कर सकता है।

बुजुर्ग ने पीया कीटनाशक, मौत

बैतूल। बोरदेही थाने के केहलपुर गांव में 60 साल के बुजुर्ग की कीटनाशक पीने से मौत हो गई। बुजूर्ग को तीन दिन पहले जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया था, जहां मंगलवार उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। मृतक के बेटे राहुल पवार ने बताया कि उनके पिता बाद इंदल पवार लंबे समय से कमजोरी और चक्कर आने की समस्या से परेशान चल रहे थे। 12 अप्रैल (शनिवार) को जब उनकी मां खेत गई हुई थी, पिता घर पर अकेले थे, इसी दौरान उन्होंने घर पर कीटनाशक पी लिया। प्रारंभिक उपचार के लिए उन्हें मुलताई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया। गंभीर हालत होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल चौकी प्रभारी विजय बड़ौदे के अनुसार, इंदल पवार को बेहोशी की हालत में भर्ती किया गया था। इस कारण उनकी मौत के पहले बयान नहीं लिया जा सका। मंगलवार को उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

कुंए में मिला महिला का शव

बैतूल। मुलताई क्षेत्र के ग्राम दातोरा में एक महिला का शव कुंए में मिला। महिला 14 अप्रैल की रात से लापता थी। परिवार के मुताबिक रात करीब 11.30 बजे सभी लोग खाना खाकर सोए थे। सुबह 6 बजे जब बेटा विपिन उठा तो मां पंचफुला बारस्कर (50) घर पर नहीं थीं। तलाश के दौरान दैय्यत बाबा मंदिर के पास स्थित खेल मैदान के कुएं में उनका शव मिला। पंचफुला पिछले 20-25 सालों से मानसिक रोग से पीड़ित थीं। उनका इलाज नागपुर अस्पताल में चल रहा था। वह अक्सर रात में इसी कुएं से पानी भरने जाती थीं। माना जा रहा है कि पानी भरते समय उनका पैर फिसल गया। बेटे विपिन और पति मारोती बारस्कर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है।

डॉ. बाबासाहेब की 134वीं जयंती मनाई

सोहागपुर। अम्बेडकर वार्ड में बाबासाहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर की 134 वीं जयंती मनाई गई।इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर माल माल्यार्पण की गई । कार्यक्रम

को कई वक्ताओं ने संबोधित करते बाबासाहेब की जीवन पर अपने-अपने विचार व्यक्त करके उनके जीवन पर प्रकाश डाला ।इस अवसर पर गणेश अहिवार ,हेमलता अहिरवार, तुलाराम अहिरवार अशोक अहिरवार ,प्रदीप अहिरवार, चैन सिंह खुराना, कुमरकांत अहिरवार, गोपाल खरे ,लेखराम अहिरवार, बालकिशन अहिरवार ,जसमन अहिरवार, अनिल खुराना अशोक खुराना, भवानी अहिरवार आदि उपस्थित थे।

अतिक्रमण से तंग आए रहवासी पहुंचे जनसुनवाई में, कलेक्टर से की कार्यवाही की मांग

बैतूल। लल्ली चौक से लेकर साईं मंदिर तक जाने वाले मार्ग पर जिला जेल की दीवार से सटे हिस्से में लोगों द्वारा पक्का अतिक्रमण कर दुकानों का संचालन किया जा रहा है। इस अतिक्रमण के कारण सडक़ की चौड़ाई काफी कम हो गई है, जिससे प्रतिदिन इस मार्ग पर जाम की स्थिति बन जाती है। खासकर सुबह और शाम के समय जब ट्रैफिक अधिक होता है, तब वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सडक़

संकरी हो जाने के कारण वाहन चालकों को आमने-सामने आने की स्थिति में रुकना पड़ता है, जिससे जाम बढ़ता चला जाता है। आए दिन यहां दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। खासकर स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह मार्ग बेहद खतरनाक बन गया है। इस समस्या से परेशान होकर आसपास के रहवासियों ने जनसुनवाई में पहुंचकर प्रशासन से शिकायत की है। नागरिकों ने बताया कि उन्होंने कई बार इस विषय में नगर पालिका के अधिकारियों को मौखिक रूप से सूचना दी, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। जनसुनवाई में पहुंचे नितिन, करण, बलवंत, आशीष और अन्य नागरिकों ने कलेक्टर से मांग की कि जेल की दीवार से सटे इस क्षेत्र में हो रहे अवैध पक्के अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए और सडक़ को पहले की तरह सुगम बनाया जाए। आवेदकों का कहना है कि यह मार्ग मुख्य बाजार और धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ है, जिससे यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं। ऐसे में यदि समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। रहवासियों ने कलेक्टर से शीघ्र प्रभावी कार्यवाही कर अतिक्रमण हटवाने और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने की मांग की है।

लठ लेकर शराब दुकान पर पहुंची महिलाएं

'लगाया शराब दुकान हटाओ गांव बचाओ का नारा'

मंदिर और आंगनबाड़ी के पास है शराब दुकान

बैतूल/ मुलताई। पवित्र नगरी मुलताई नगर में शराबबंदी लागू हुई, तो नगरीय क्षेत्र से शराब दुकानें हटा दी गई है, किंतु इसके साथ ही क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकाने और ग्रामों के गली मोहल्लों में बिकती अवैध शराब, ग्रामीण क्षेत्रों का माहौल बिगाड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र के गली मोहल्ले में बिकने वाली अवैध शराब नई पीढी को नशे का आदी बना रही है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक और विशेष तौर से महिलाओं में भारी आक्रोश है। मंगलवार को छिंदवाड़ा रोड पर स्थित ग्राम रिधोरा शराब दुकान से परेशान गांव की महिलाओं का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में महिलाएं लाठियां लेकर रिधोरा गांव की शराब दुकान पर पहुंचीं और ताला जड़ दिया। गुस्साई महिलाओं ने सेल्समैन को भी दुकान के अंदर बंद कर दिया और चेतावनी दी कि जब तक यह दुकान नहीं हटेगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। महिलाओं ने पूरे गांव में रैली निकाली, ढोल-नगाड़ों और नारों के साथ महिलाओं को जोड़ा और बढ़ी तो सीधा शराब दुकान पहुंचकर धरना दे दिया। ग्राम महिलाओं के शराब दुकान हटाओ गांव बचाओ जैसे नारों से गूंज उठा।

रात में घर से निकलने में लगता है डर- ग्रामीण क्षेत्रों में बिकती शराब ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। रिधोरा में शराब दुकान बंद करने को लेकर आंदोलन कर रही,महिलाओं ने बताया कि शराब दुकान दुर्गा मंदिर, गायत्री मंदिर, शिव मंदिर और आंगनबाड़ी केंद्र के पास है। शराब पीकर वहां आने वाले लोग गाली-गलौच और हंगामा करते हैं। शाम होते ही महिलाएं और बच्चियां घर से बाहर निकलने से डरने लगी हैं। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि शराब पीने के बाद शराबी लोग गंदी-गंदी गालियां और महिलाओं पर फत्तीयां कसते है।

प्रशासन मौन, महिलाएं गरज उठीं- प्रदर्शन में सुखवंती बाई, किरण बाई, रुक्मिणी बाई, मुनी बाई और कल्पना बाई समेत कई महिलाएं शामिल रहीं। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई शून्य रही। इस उपेक्षा के खिलाफ अब गांव की महिलाएं आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। महिलाओं ने प्रदर्शन कर शराब दुकान को हटाने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि शराब पीने के बाद शराबी वाद-विवाद करते है। जिससे गांव का माहौल बिगड़ रहा है।

आबकारी नियमों के बजाए, स्वयं तय कर रहे शराब की कीमत

बैतूल। शाहपुर स्थित वाइनशॉप पर प्रिंट रेट से अधिक दामों पर शराब की बिक्री की जा रही है। नए ठेके होने के बाद शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं और शासन द्वारा निर्धारित एमआरपी को एक तरफ कर अपनी मर्जी से दाम तय कर ग्राहकों को शराब बेची जा रही है। इस मामले के सामने आने के पश्चात पत्रकार अशीष राठौर और अन्य लोगों के साथ पहुंच कर मौके पर शराब की एक बोतल ली गई एवं उसकी कीमत पूछने पर दुकान संचालक द्वारा 1500 रुपए बताया गया। सिग्नेचर ब्रांड की शराब की बोतल पर एमआरपी 1395 अंकित थी, जबकि कीमत को लेकर दुकानदार से बात की गई, तब उनका कहना था कि हम इसी कीमत पर देते हैं, आपको लेना हो तो लें अन्यथा मत लीजिए। इसी के साथ अन्य दूसरी शराब के विषय में जानकारी लेने पर भी यही हाल था। शराब की बोतल पर दूसरे ब्रांड पर भी 100 से 500 रुपए तक अधिकतम खुदरा मूल्य लिया जा रहा था। शिकायतकर्ता द्वारा सबूत के तौर पर फोन पे से 1500 का भुगतान कर सिग्नेचर बोतल खरीदी गई। बिल मांगने पर बिल बुक न छपने की बात कहकर शराब दुकान संचालक द्वारा टालमटोली की गई। साथ ही निर्धारित मूल्य सूची भी दुकानों के सामने नहीं लगाई थी। शाहपुर में दो शराब दुकान संचालित है। दोनों पर ही निर्धारित मूल्य के बोर्ड नहीं है।

इनका कहना है-

हमे शासन द्वारा गोदाम से जो माल दिया जा रहा है, वह पुराने एमआरपी का स्टॉक है, परंतु उस पर हमे शासन को नये रेट से ड्यूटी देना होता है तथा हमे जो बिलिंग हो रही है, वह नये रेट से हो रही है। इसे लेकर समस्या है। हाल ही में शराब का ठेका चेंज होने से बिल बुक न छपने से समस्या है। सिर्फ हमारी दुकान पर ही नहीं, अपितु पूरे मप्र में नये रेट पर बिलिंग हो रही है, भले शराब की बोतल पर पुराने रेट प्रिंट हो।

- नंदकिशोर शर्मा, संचालक, शराब दुकान

ध्यान आत्मा का स्वरूप है, इससे ही मिलती है सच्ची शांति: नर्मदा प्रसाद मिश्रा

बैतूल। गंज स्थित ई.एफ.ए. शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 64 कलाओं पर आधारित कौशल शिविर में छात्राओं को योग एवं ध्यान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस शिविर का आयोजन विद्यालय के प्राचार्य ललित लाल लिल्होरे के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। शिविर के प्रभारी शिक्षक महेश गुंजेले ने जानकारी देते हुए बताया कि यह शिविर 12 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और इसमें विद्यालय की 100 से अधिक छात्राएं नियमित रूप से भाग ले रही हैं।

15 अप्रैल को विशेष सत्र में जिला योग प्रभारी नर्मदा प्रसाद मिश्रा द्वारा छात्राओं को योग एवं ध्यान की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने छात्राओं को बताया कि ध्यान केवल शांति पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मिक विकास का भी आधार है। ध्यान सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। इससे छात्राओं के प्रदर्शन में भी सुधार आता है। ध्यान से तनाव और चिंता कम होती है, जिससे विद्यार्थी अपने समय का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। नर्मदा प्रसाद मिश्रा ने कहा कि ध्यान मानसिक रूप से गहरी शांति प्रदान करता है। ध्यान अग्नि की तरह है, जो बुराइयों को जलाकर नष्ट कर देता है। यह धर्म और योग की आत्मा है। जो ध्यान से जुड़ा होता है उसकी मृत्यु नहीं होती, जबकि ध्यान से दूर व्यक्ति को बुढ़ापे में मृत्यु का भय सताने लगता है। ध्यान से ही हम अपने खोए हुए स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। यह विचारों पर नियंत्रण स्थापित करने और आत्मिक शक्ति को विकसित करने में सहायक है। कार्यक्रम के दौरान मिश्रा ने छात्राओं को ध्यान के विभिन्न अभ्यास भी कराए। योग एवं ध्यान का यह विशेष प्रशिक्षण सत्र 30 अप्रैल तक नियमित रूप से जारी रहेगा, जिसमें छात्राओं को शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

ज्ञानदान अभियान के तहत भौरा में पुस्तकालय की शुरुआत

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब ग्रामीण बच्चों को मिलेगा संसाधन

बैतूल/ भौरा। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मुख्य कार्यपालन अधिकारी हर्षिका सिंह की पहल पर प्रदेशभर में ज्ञानदान अभियान प्रारंभ किया गया है। इसी कड़ी में मंगलवार को मिशन द्वारा ग्राम भौरा में उन्नति महिला संकुल स्तरीय संगठन अंतर्गत नारी शक्ति ग्राम संगठन के कार्यालय में अध्ययन हेतु पुस्तकालय की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संसाधनों से जोडक़र उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सक्षम बनाना है।यह आयोजन जिला परियोजना अधिकारी सतीश पवार के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शाहपुर विकासखंड की ब्लॉक नोडल अधिकारी प्रीति तिवारी, प्रियंका उपराले, संकुल संगठन की अध्यक्ष, सचिव, प्रबंधक सहित अन्य स्व-सहायता समूहों की महिलाओं की सक्रिय सहभागिता रही। नव आरंभित पुस्तकालय में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), नर्सिंग, बैंकिंग एवं अन्य प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अध्ययन सामग्री के साथ-साथ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई हैं। इन पुस्तकों की व्यवस्था जनसहयोग के माध्यम से की गई है तथा आगामी समय में भी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पुस्तकें संग्रहित की जाएंगी। पुस्तकालय का संचालन नारी शक्ति ग्राम संगठन द्वारा किया जाएगा, जहां कोई भी विद्यार्थी आकर निःशुल्क अध्ययन कर सकता है। यह सुविधा विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, जो महंगे कोचिंग संसाधनों का लाभ नहीं ले सकते।

जनसहयोग से होगा पुस्तकालय का विस्तार - नारी शक्ति ग्राम संगठन भौरा की प्रबंधक पूनम पासी ने समाज के प्रबुद्धजनों से अपील की है कि वे अपने घरों में उपलब्ध उपयोगी प्रतियोगी पुस्तकों को पुस्तकालय हेतु दान करें। पुस्तकों का दान सबसे श्रेष्ठ दान है। आप जो पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हैं, वे किसी जरूरतमंद बच्चे का भविष्य बना सकती हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस अभियान से जुडक़र ग्रामीण शिक्षा को सशक्त बनाने में सहयोग करें। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वावलंबन की दिशा में एक प्रभावी कदम माना जा रहा है। जनभागीदारी से संचालित यह पुस्तकालय भविष्य में अनेक होनहार प्रतिभाओं को सशक्त आधार प्रदान करेगा।

सोहागपुर के पुरातात्विक इतिहास पर व्याख्यान माला 18 अप्रैल को

सुबह सवेरे सोहागपुर। विश्व विरासत दिवस के अवसर पर 18 अप्रैल को दोपहर 12बजे से विवेकानंद एकेडमी में सोहागपुर के पुरातात्विक इतिहास महत्व, संरक्षण , जागरूकता पर व्याख्यान, प्रदर्शनी एवं छात्रों के लिये प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह के मुख्य आतिथ्य एवं नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमति लता यशवंत पटेलकी अध्यक्षता में संपन्न होगा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि समाजसेवी कन्नूलाल अग्रवाल , क्षेत्रीय निदेशक भा . पु.स.डॉ. भुवन विक्रम, यूं .के.डॉ. अध्यापक मिश्रा विक्रम ,उप अधीक्षण पुरातत्वविद् डॉ. जलज कुमार तिवारी , सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद्, मंदिर सर्वेक्षण परियोजना उ.क्षे.डॉ. राजेश कुमार मेहर आदि रहेंगे।

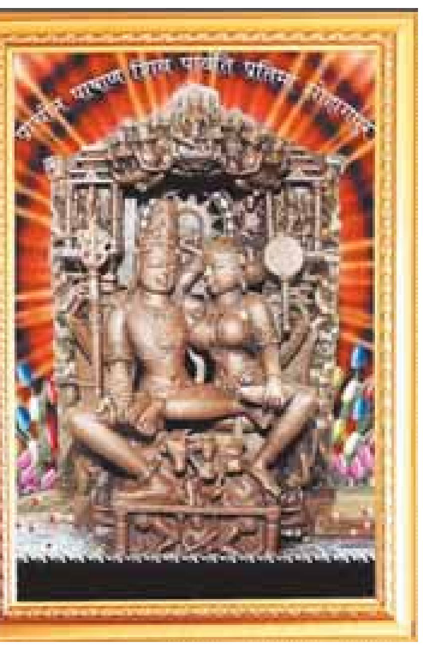

विवेकानंद एकेडमी संचालक अनिल गहरैया एवं अधिवक्ता प्रांजल तिवारी ने बुद्धिजीवियों से उक्त कार्यक्रम में सहभागिता निभाने का आग्रह करने के साथ कहा है कि ऐतिहासिक महत्व की पुर्नस्थापना के लिये यह व्याख्यान माला मील का पत्थर साबित होगी।

उल्लेखनीय है कि सोहागपुर नगर को लेकर कई किवदंतियां प्रचलित हैं। कि सोहागपुर ही वाणासुर की नगरी है। सोहागपुर गोंडवाना राजाओं की नगरी है।परमार वंश का उल्लेख होता रहता है। वहीं यह भी उल्लेखनीय है कि सोहागपुर क्षेत्र में खुदाई के समय की प्रतिमाएं निकलती रहती हैं। आज भी जगह-जगह प्रतिमाएं क्षेत्र में बिखारी हुई हैं। वरिष्ठ वकील स्वर्गीय प्रेमशंकर तिवारी के खेत में 16 सदीं की शिव पार्वती सहित ओमकार आरती के अनुरूप की पाषाण प्रतिमा निकली थी।

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मेहंदी प्रतियोगिता

सुबह सवेरे सोहागपुर। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् के तत्वावधान में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कक्षाओं में सभी छात्राओं के लिए मेंहदी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत उपस्थित सभी छात्राओं ने एक दूसरे के हाथों में जल गंगा संवर्धन अभियान प्रचार प्रसार के उद्देश्य को लेकर मेहंदी लगाई गई। इस अवसर पर छात्राआयुषी कुशवाहा ने मेंहदी के माध्यम से संदेश दिया कि वर्षा का जल हम यदि संरक्षित नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में भविष्य में हमें नदी तालाबों की फोटो ही देखने को मिलेंगे। छात्रा वंशीका भावसार ने कहा कि जब तक पेड़ों का संरक्षण नहीं होगा। तो वर्षा भी नहीं होगी। और वर्षा होती है । यदि वर्षा का पानी भी नहीं रुकेगा। ऐसी परिस्थिति में पानी भी विलुप्त हो जाएगा । तथा मिट्टी का कटाव होता रहेगा। कार्यक्रम का आयोजन विकास खंड समन्वयक किशोर कड़ोले के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ?। आयोजन में शिवानी, वर्षा, सीमा ,प्राची, नेहा , रंजना, शिवनी कुशवाहा, चांदनी, शिविका कुशवाहा उदय आदि ने प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में छात्रा आयुषी प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर वंशी भावसार रही।इस अवसर पर गजेंद्र ठाकुर, श्याम मीना, सचिन विश्वकर्मा मंजु व निशा चौरसिया मेंटर आदि उपस्थित थे।

जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन की गतिविधियों में गति लाएं: कलेक्टर

प्रत्येक पात्र व्यक्ति को स्वरोजगार मूलक योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए बैंकवार कैंप आयोजित करें

बैतूल। जनसहभागिता से जल स्त्रोतों के संरक्षण और संवर्धन की गतिविधियों में गति लाएं। अमृत सरोवर, खेत तालाब, सोखपीट इत्यादि जल संरचनाओं के निर्माण में प्रगति लाएं और उन्हें समय पर पूरा करें। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की जल संरचनाओं, बावडिय़ों की सघन साफ-सफाई और मरम्मत कराएं। यह निर्देश कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित समयसीमा की बैठक में समस्त सीएमओ, जनपद सीईओ और अन्य संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान की विस्तृत समीक्षा कर कहा कि सभी एसडीएम अपने क्षेत्र की जल संरचनाओं की मैपिंग कराएं। साथ की जल संरचनाओं पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर उन्हें तत्काल हटवाएं। उन्होंने शिक्षा विभाग को जल संरचनाओं, जलीय जीवन, जल परम्पराओं पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने क्षेत्र में पंचायत के अमले के सहयोग से आधार खसरा लिंकिंग का अभियान चलाएं और शत प्रतिशत आधार खसरा लिंकिंग पूर्ण कराएं। उन्होंने स्वरोजगार मूलक योजनाओं से हर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए बैकवार कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कैंप में ही हितग्राहियों के प्रकरण तैयार करने से लेकर उन्हें स्वीकृत और वितरित कराएं। कैंप के आयोजन के लिए नोडल महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र होंगे।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने राशन प्राप्त हितग्राहियों के ई-केवाईसी अभियान की भी ब्लॉकवार जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी जनपद सीईओ, सीएमओ और एसडीएम पूरी गंभीरता से अभियान में कार्य करें और राशन प्राप्त हितग्राहियों के प्रत्येक परिवार सदस्य का ई केवाईसी कराएं। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की विभागवार समीक्षा कर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण करने के निर्देश सभी विभागों को दिए। उन्होंने कहा कि 50 दिवस से अधिक की शिकायतों के निराकरण पर भी सभी अधिकारी विशेष ध्यान दें। उन्होंने तकनीकी शिक्षा, उप संचालक उद्यानिकी, जेल विभाग, श्रम विभाग , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को शिकायतों के निराकरण में विशेष देने के निर्देश दिए।

उन्होंने निर्देशित किया कि सभी जनपद सीईओ को श्रम विभाग की संबल योजना, ईपीओ, भवन निर्माण सम्बन्धी शिकायतों का त्वरित निराकरण कराएं । इसी प्रकार समग्र सम्बन्धी शिकायतों का भी निराकरण जल्द कराएं। सभी एसडीएम भी अपने क्षेत्र के बीएमओ से हितग्राहियों की राशि भुगतान संबंधी शिकायतों का निराकरण कराएं। टीएल बैठक और जनसुनवाई में अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बैतूल का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन, अपर कलेक्टर राजीव नंदन श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर मकसूद अहमद सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित रहें।

एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह को चिकित्सा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए लखनऊ में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन COMET-2025 (कॉन्क्लेव ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज़ एंड ट्रॉमा) में सम्मानित किया गया। यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सोसाइटी ऑफ एक्यूट केयर ट्रॉमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन (SACTEM) द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें भारत, यूनाइटेड किंगडम, अबूधाबी, सऊदी अरब, नेपाल समेत विश्वभर के आपातकालीन चिकित्सा एवं ट्रॉमा विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान, प्रो. सिंह ने एक महत्वपूर्ण सत्र "बिग क्राउड्स, बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी: द साइंस ऑफ इवेंट मेडिसिन" की अध्यक्षता भी की।

यूटीएस ऐप से आसान सफर

भोपाल मंडल में लाखों यात्रियों ने लिया डिजिटल सुविधा का लाभ

भोपाल। यात्रियों की सुविधा एवं अनारक्षित टिकट प्रणाली को और अधिक सहज एवं डिजिटल बनाने की दिशा में यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। भोपाल मंडल रेल प्रशासन द्वारा इस मोबाइल ऐप के प्रति यात्रियों को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाए गए प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता अभियान के सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि मार्च 2025 में भोपाल मंडल के अंतर्गत यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से कुल 40,033 टिकटों की बुकिंग की गई, जिनके जरिए 2 लाख 6 हजार 607 यात्रियों ने यात्रा की। इस डिजिटल माध्यम से मंडल को कुल 46 लाख 27 हजार 255 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि आम यात्रियों के बीच डिजिटल टिकटिंग के प्रति विश्वास बढ़ रहा है और वे तेजी से मोबाइल ऐप की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

भोपाल मंडल के रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट के लिए यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप की सुविधा सहजता से उपलब्ध है। यह ऐप यात्रियों को लंबी कतारों से मुक्ति दिलाते हुए, कहीं से भी टिकट बुक करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके अलावा यह पर्यावरण हितैषी विकल्प भी है क्योंकि इससे कागज़ रहित टिकटिंग को बढ़ावा मिलता है।

एक ही रस्सी पर युवक और किशोरी ने लगाई फांसी

बड़वानी (नप्र)। निवाली थाना क्षेत्र में खेतिया रोड स्थित कन्या खेल परिसर के सामने एक मकान में युवक एवं किशोरी द्वारा एक ही रस्सी पर फांसी लगाने से दोनों की मौत हो गई। निवाली थाना प्रभारी रामकृष्ण लौवंशी ने बताया कि खेल परिसर के सामने निवासी वीरेंद्र मेहता द्वारा थाने पर आकर घटना की जानकारी देते हुए बताया गया कि उसके भतीजे का दोस्त किसी रिश्तेदार की शादी में से निवाली लड़की को लेकर उसके मकान पर सोमवार की रात को आया था। लड़के का नाम अर्जुन पुत्र राजू (20) निवासी कुंडिया वरला थाना एवं नाबालिग सोलह वर्षीय लड़की बिस्टान थाने खरगोन की रहने वाली है। मंगलवार को दोनों लड़का एवं लड़की ने एक ही रस्सी का फंदा बनाकर दोनों ने फांसी लगा ली। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। फारेंसिक टीम खरगोन एवं फिंगरप्रिंट टीम बड़वानी को घटनास्थल निवाली बुलाकर साक्ष जुटाए गए।शाम चार बजे के करीब लड़का एवं लड़की के माता-पिता को बुलाकर दोनों को फांसी के फंदे से उतार कर निवाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया।जहां पर चिकित्सकों द्वारा दोनों का पोस्टमार्टम किया। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर शव माता-पिता को सौंपे। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही है।

सातवां पोषण पखवाड़ा 22 अप्रैल तक

हरदा (निप्र)। प्रदेश में व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से कुपोषण को कम करने के लिए पोषण अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष पोषण अभियान के तहत पोषण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। इस वर्ष सातवां पोषण पखवाड़ा 8 से 22 अप्रैल तक मनाया जाएगा। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'जीवन के प्रथम 1000 दिवस' पोषण ट्रैकर में लाभार्थी मॉड्यूल को लोकप्रिय बनाने व्यापक प्रचार-प्रसार, समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन मॉड्यूल के माध्यम से कुपोषण का प्रबंध तथा बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को अपने पर बाल जैसे थीम पर केंद्रित विभिन्न गतिविधियों को आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। पोषण पखवाड़ा के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र सेक्टर, परियोजना एवं जिला स्तर की गतिविधियों में स्थानीय पोषण संसाधनों की को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, सामुदायिक जागरूकता और पोषण संवेदनशील कार्यक्रम जैसे आयोजन किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए महत्वपूर्ण निर्णय

अन्नदाता मिशन को दी गई स्वीकृति, सतना में अस्पताल बनेगा

भोपाल (नप्र)। डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में अन्नदाता मिशन को मंजूरी दी गई।

किसानों को सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार उनकी आय बढ़ाने के रास्ते खोज रही है। पशुपालन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। फसल बीमा योजना का लाभ शत-प्रतिशत किसानों को दिलाने के साथ सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए सरकार ने कार्य योजना बनाई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में अन्नदाता मिशन को दी गई स्वीकृति। किसानों की आय बढ़ाने के लिए किए गए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनाई जाएगी उच्च स्तरीय समिति। जिला स्तर पर भी बनेगी कमेटी।

इन निर्णयों पर लगी मुहर

- किसानों को खेती के शासक पशुपालन, उद्यानिकी आदि क्षेत्र में भी किया जाएगा प्रोत्साहित।
- खाद्य प्रसंस्करण को भी दिया जाएगा बढ़ावा।
- भोपाल के गांधी मेडिकल कालेज में पैट्रियोटिक डिपार्टमेंट प्रारंभ करने की स्वीकृति।
- सतना में अस्पताल बनेगा।
- लाडली बहन योजना बंद नहीं होगी।
- अब प्रतिमाह 10 से 15 तारीख के बीच होगा राशि का अंतरण।

पन्ना में किसान के घर में लगी आग

डेढ़ लाख रुपए समेत घर का सारा सामान जला, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू

पन्ना (नप्र)। पन्ना जिले के अजयगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम चंपतपुर में एक किसान के घर में भीषण आग लग गई। मंगलवार दोपहर 2 बजे भोला लोध के घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। फसल बेचने के बाद घर में रखे डेढ़ लाख रुपए नगद भी आग की भेंट चढ़ गए। आग की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंच पाई। ग्रामीणों की मदद से बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। तब तक घर में रखा सारा सामान जल चुका था। पीड़ित किसान भोला लोध ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

प्रदेश के हर क्षेत्र में उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के लिए सरकार प्रतिबद्ध : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में ग्वालियर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण योजना की गहन समीक्षा की उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जल संसाधन मंत्री एवं ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह और ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने जय आरोग्य अस्पताल, ग्वालियर में सीटीवीएस (कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी) विभाग के आवश्यक पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव तैयार करने और अस्पताल भवन के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों को शीघ्रता एवं प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिकित्सकीय सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में ग्वालियर क्षेत्र के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के अधोसंरचना विकास, मैन पॉवर, उपकरण उपलब्धता की विस्तारपूर्वक समीक्षा कर आवश्यक व्यवस्थाओं के उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश सरकार समस्त अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि नागरिकों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बाहर न जाना पड़े। इसके लिए आवश्यक अधोसंरचना विकास, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और चिकित्सकीय स्टॉफ की पर्याप्त नियुक्ति सुनिश्चित की जा रही है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत सांवेर विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, आयुक्त श्री तरुण राठी, तथा संचालक श्री नीरज कुमार सिंह उपस्थित रहे।

'तालाबों और कुओं को साफ रखें, वर्षा जल संचयन करें'

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है। प्रदेश के जिलों में जल स्रोतों के संवर्धन और संरक्षण के लिये विविध गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अभियान में जनभागीदारी से जल संरक्षण का संकल्प साकार हो रहा है। प्राचीन जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार और नवीन जल संरचनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

उमरिया में वाटर शेड महोत्सव- उमरिया जिले के जनपद पंचायत करकेली में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आयोजित वॉटरशेड महोत्सव-2025 जल संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल रही। कार्यक्रम में विधायक शिवनारायण सिंह, कलेक्टर श्री धरणेन्द्र जैन, जनप्रतिनिधि, किसान, पंचायत प्रतिनिधि, महिला स्व-सहायता समूह, युवा, छात्र-छात्राएं, और स्थानीय जन मौजूद रहे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 का उद्देश्य 'हर खेत को पानी' देना है, ताकि किसानों को वर्ष भर सिंचाई की सुविधा मिल सके और खेती की उत्पादकता में वृद्धि हो। योजना के अंतर्गत वाटरशेड डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण घटक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, भूजल स्तर को बढ़ाने और भूमि सुधार जैसे

कार्यों पर केन्द्रित है।

देवास में तालाब के गहरीकरण से पानी का होगा संचय, वॉटर लेवल भी बढ़ेगा- देवास जिले में प्रशासन एवं ग्रामीणों के जनसहयोग से जनपद पंचायत देवास की ग्राम पंचायत टिगरिया गोगा एवं पर्वतपुरा के तालाब का गहरीकरण किया जा रहा है। इस तालाब के गहरीकरण होने से बारिश के दिनों में अधिक पानी का एकत्रितकरण होगा तथा वॉटर लेवल भी बढ़ेगा। इससे पेयजल के साथ खेती करने के लिए भी पानी मिल सकेगा।

छतरपुर में प्रताप सागर तालाब की सफाई- छतरपुर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। ग्राम निवरिया में ग्रामीण लोगों की बैठक कर लोगों को तालाबों, कुएं एवं बावड़ियों की सफाई करने के लिए प्रेरित किया गया और श्रमदान करने की शपथ दिलाई गई। प्रताप सागर तालाब की सफाई अभियान का कार्यक्रम कराया गया। राजनगर अंतर्गत बसारी के ग्राम भैरा में श्रमदान किया गया।

धार के जलगंगा अभियान में युवाओं ने दिखाया सामाजिक उत्तरदायित्व- धार एवं तिरला विकासखंड में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। धार के जीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सीएमसीएलडीपी के छात्र-छात्राएं, नवांकुर समिति, सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद ग्राम जेतपुरा स्थित तालाब की सफाई के लिये श्रमदान किया गया। इसमें सभी छात्रों और अतिथियों ने भाग लेकर जल संरक्षण का संदेश दिया।

शहडोल में दीवार लेखन कर महिलाएं बता रही जल का महत्व- जल गंगा संवर्धन अभियान अब जन अभियान बनता जा रहा है। शहडोल जिले के ब्यौहारी की महिलाओं ने 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के तहत जल का महत्व बताने के लिए दीवार पर नारे लिखें तथा जल के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

श्रमिकों का कल्याण प्रशासनिक नहीं, नैतिक उत्तरदायित्व: श्रम मंत्री पटेल

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल संचालक मण्डल की 62वीं बैठक हुई

भोपाल (नप्र)। श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मंडल की बैठकों में श्रम कल्याण के विषय पर विस्तारसे चर्चा की जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि आगामी बैठक में श्रम कल्याण योजनाएं एवं श्रम कानूनों में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं के बारे में बोर्ड में चर्चा की जाए। उन्होंने कहा कि संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की विसंगतियों को दूर करें। मंत्री श्री पटेल मंगलवार को पलाश रेसीडेंसी में मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल के संचालक मण्डल की 62वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्रम कल्याण से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव, अपर सचिव श्री बसंत कुर्रे, कल?याण आयुक?त श्री एस.एस.दीक्षित सहित मंडल के सदस्य, विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि श्रमिकों का कल्याण केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, नैतिक उत्तरदायित्व भी है। हमारी सरकार हर श्रमिक के सम्मान, अधिकार और भविष्य की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले शत-प्रतिशत श्रमिकों को सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक वाहन का वितरण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नवीन श्रम कल्याण केंद्रों की डिजाइन भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की जाए। बैठक में प्रमुख सचिव, श्रम श्री उमराव ने जानकारी दी कि शासन की ओर से मंडल को अंशदान राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 12 करोड़ की गई है।

बैठक में मण्डल की 61वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कार्यालय ?द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि की गई एवं मण्डल के वित्तीय बजट वर्ष 2025-26, मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। मण्डल कर्मचारियों की सेवाशर्तों विनियम में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किये जाने, म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 2 (3) (ख) को संशोधित करने, मण्डल के नियमित कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के एरियर्स के व्यय भार की स्वीकृति प्रदान की गई, श्रम कल्याण केन्द्र, बुरहानपुर भवन, बुरहानपुर के मरम्मत के लिए व्यय राशि पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

ओवरब्रिज बनने से लाखों लोगों को मिलेगी ट्रैफिक की समस्या से राहत: मंत्री श्रीमती गौर

आशिमा मॉल से बावड़िया कलां के बीच ओवरब्रिज निर्माण जून से होगा प्रारंभ

भोपाल(नप्र)। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने मंगलवार को मंत्रालय में विभिन्न विभागों के साथ गोविंदपुरा क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों में देरी और लापरवाह अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए समय सीमा में कार्य करने के निर्देश दिए।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि आम लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए आशिमा मॉल से बावड़िया कलां के बीच ओवरब्रिज बनाया जाएगा। इसका लाभ रोज आवागमन करने वाले लाखों लोगों को मिलेगा। ओवरब्रिज के निर्माण के लिए इसी सप्ताह टेंडर जारी हो जाएगा और जून महीने में इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने बावड़िया ब्रिज पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने के निर्देश भी दिए हैं, इससे लंबे जाम से रहवासियों को राहत मिलेगी।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि भेल क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत के लिए भेल के अधिकारियों के साथ समन्वय कर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी इस कार्य को जल्द पूरा करें। उन्होंने लंबे समय से एमजीएम स्कूल अवधपुरी के करीब बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य में देरी पर कहा कि सड़क के निर्माण कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया। पिपलानी से खजूरी कलां तक 4 किलोमीटर लंबी नाली के निर्माण कार्य को भी बारिश से पहले पूरा करने के भी राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने आनंद नगर से ट्रांसपोर्ट नगर तक बन रही लगभग 5 किलोमीटर की सड़क के अधूरे निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिये कहा।

पूर्व मुख्य सचिव, म.प्र.एंथोनी डिसा को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया

भोपाल। प्रसिद्ध लेखक और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी की कहानी ' ' ('इमली') को 54 देशों की 8,000 से अधिक प्रविष्टियों में से शीर्ष 25 में स्थान मिला। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और चर्चित लेखक श्री एंथोनी डिसा ने एक बार फिर अपनी उपलब्धियों की फेहरिस्त में एक और प्रतिष्ठित सम्मान जोड़ लिया है। 'टीनो डिसा' के नाम से लेखन करने वाले श्री डिसा की कहानी ('इमली') को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त मान्यता उनकी प्रशासनिक सेवा और साहित्यिक लेखन–दोनों में उनकी गहराई और सृजनात्मकता को दर्शाती है।

54 देशों से आई 8,000 से अधिक प्रविष्टियों में से चुनी गई 25 श्रेष्ठ कहानियों में 'इमली' को स्थान मिला है, जिसे पांच अंतरराष्ट्रीय निर्णायकों की एक समिति ने चयनित किया। लंदन में 15 अप्रैल को शॉर्टलिस्ट की घोषणा की गई, जबकि विजेता का नाम जून में घोषित किया जाएगा। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ को प्रायः 'शॉर्ट स्टोरी का बुकर पुरस्कार' कहा जाता है और यह अंग्रेज़ी साहित्य की सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में से एक है। केवल शॉर्टलिस्ट में शामिल होना भी स्वयं में एक वैश्विक सम्मान माना जाता है।

'इमली' कहानी मध्यप्रदेश के एक काल्पनिक ग्रामीण क्षेत्र में आधारित है और श्री डिसा की अधिकांश रचनाओं की तरह इसमें भी अंत में एक गहरा मोड़ है। यह कहानी उनकी कथा-कौशल के साथ-साथ भारतीय ग्रामीण और सांस्कृतिक जीवन की गहरी समझ को भी उजागर करती है।

एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में श्री एंथनी डिसा ने राज्य और केंद्र स्तर पर कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, और अपने प्रशासनिक जीवन के अंत में मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपनी रचनात्मक ऊर्जा और सामाजिक संवेदना को साहित्यिक अभिव्यक्ति में रूपांतरित किया, जो उनके कहानी लेखन और कविता में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

अब तक उनके तीन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं–दो कहानी संग्रह- 'The Disrobing of Draupadi' और 'One For Sorrow, Two For Joy', और एक बच्चों के लिए रहस्य कथा 'The Curious Case of the Nandikote Nawab', जिसे कतिपय CBSE स्कूलों ने अपनी पठन सूची में शामिल किया है। उनकी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ, भावनात्मक गहराई और कथानक की रोचकता का सुंदर संयोजन देखने को मिलता है।

श्री डिसा को 2017 और 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय लघुकथा प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। वे दो कहानियाँ भी मध्य प्रदेश में आधारित हैं - एक पंचमढ़ी में और एक प्राचीन काल के उज्जैन में।उनके काव्य-संग्रहों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है और हाल ही में लंदन से प्रकाशित एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका में उनकी दो कविताएं प्रकाशित हुई हैं।

वर्तमान में वे अपनी अगली लघुकथा संग्रह पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें वे भारतीय जीवन के विविध पक्षों को अपनी साहित्यिक दृष्टि से उजागर कर रहे हैं।

एक समर्पित प्रशासनिक अधिकारी से लेकर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त लेखक बनने की उनकी यात्रा इस बात का प्रेरणादायक उदाहरण है कि किस प्रकार बौद्धिक चेतना और रचनात्मकता सेवा-निवृत्त जीवन में भी नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है।

॥ मंदिरम् ॥

84

मेनाल महानालेश्वर मंदिर, राजस्थान

मेनाल महानालेश्वर मंदिर राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जो चित्तौड़गढ़ से लगभग 90 किलोमीटर और बूंदी से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर को इसके पुराने नाम महानालेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित मेनाल शिव मंदिर को मिनी-खजुराहो मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। मेनाल महानालेश्वर मंदिर 11वीं सदी का एक चमत्कार है जो देखने लायक है। शाकंभरी राजवंश के सोमेश्वर चाहमान और उनकी रानी सुहावदेवी ने 11वीं शताब्दी ईस्वी में इस मंदिर परिसर का निर्माण कराया था। ये शिव मंदिर, जिन्हें महानालेश्वर के नाम से जाना जाता है, चाहमान शासन के दौरान शैव धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र था।

म.प्र.में वन पुर्नस्थापन पर दो दिवसीय कार्यशाला

केंद्रीय मंत्री और सीएम करेंगे शुभारंभ, वन सुरक्षा में वनवासी समुदाय की भूमिक पर होगी चर्चा

भोपाल (नप्र)। भोपाल के नरोन्हा प्रशासन अकादमी में कार्यशाला के शुभारंभ सत्र की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सत्र में मुख्य वक्तव्य देंगे।

भोपाल के नरोन्हा प्रशासन अकादमी में कार्यशाला के शुभारंभ सत्र की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सत्र में मुख्य वक्तव्य देंगे।

मध्यप्रदेश के आदिवासी इलाकों में वन पुर्नस्थापन, जलवायु परिवर्तन और समुदाय-आधारित आजीविका जैसे

विषयों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 18 अप्रैल से शुरू होगी। राजधानी के नरोन्हा प्रशासन अकादमी में होने वाली कार्यशाला के शुभारंभ सत्र की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। इस दौरान केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सत्र में मुख्य वक्तव्य देंगे।

राष्ट्रीय कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में वन संरक्षण की वर्तमान कानूनी व्यवस्थाएं, उनकी सीमाएं और समाधान, जैव विविधता संशोधन अधिनियम-2023, सामुदायिक वन अधिकार, पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण और वन पुर्नस्थापन जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। बैंगलुरू से आ रहे प्रो. रमेश विशेषज्ञ वक्तव्य भी देंगे।

कार्यशाला में डॉ. योगेश गोखले, डॉ. राजेन्द्र दहातोंडे आदि वक्ता विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे।

रामदेव के खिलाफ थाने पहुँचे दिग्विजय सिंह

शरबत बयान के खिलाफ शिकायत की

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ भोपाल के टीटी नगर थाने में मंगलवार को शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाबा रामदेव ने अपने उत्पादों के प्रचार के दौरान ऐसी टिप्पणी की है, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

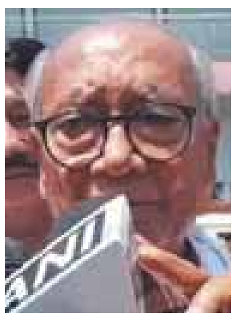

बता दें कि बाबा रामदेव ने हाल ही में अपने एक शरबत के प्रचार के लिए देश के एक प्रतिष्ठित शरबत ब्रांड पर यह कहते हुए टिप्पणी की थी कि उस ब्रांड को खरीदने से देश में मदरसे बनेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा जिसने यह बयान दिया है, मौजूदा कानून के तहत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैं एक सप्ताह तक इंतजार करूंगा, यदि कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। इस मामले पर अतिरिक्त डीसीपी रश्मि अग्रवाल दुबे ने पुष्टि करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह लिखित शिकायत की है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि बयान और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सीएम के मंच पर जगह नहीं मिली, आदिवासी विधायक नाराज

बोले–महापौर मंच पर बैठे, मैं बिरसा मुंडा, टंट्या भील का वंशज हूं, मुझे नहीं बैठाया

रतलाम (नप्र)। रतलाम में आयोजित अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन सीएम डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए। इस दौरान रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामोर मंच पर जगह नहीं मिलने से नाराज हो गए।

गुस्से में डामोर कार्यक्रम छोड़कर अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ लौटने लगे। इस पर भाजपा नेता विनोद कर्मचंदानी और सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की। डामोर ने कहा-मैं रतलाम ग्रामीण का विधायक हूं, बिरसा मुंडा और टंट्या भील का वंशज हूं, मुझे ही मंच पर नहीं बैठाया। जबकि, महापौर मंच पर बैठे हैं। मुझे नीचे ऐसी जगह बैठाया, जहां हवा भी नहीं आ रही।

आयोजक बोले- चूक हुई है, विधायक को मना लेंगे- कार्यक्रम के आयोजक और वनवासी ग्रामीण मजदूर संघ के प्रभारी जयंतीलाल ने कहा कि कहीं न कहीं चूक तो हुई है। विधायक हमारे हैं, हम उनके पास जाएंगे, क्षमा मांगकर उन्हें मना लेंगे।

उज्जैन के पास खुलेआम शराब पीने का वीडियो

पीसीसी चीफ पटवारी ने कहा– शराबबंदी कागजों में, 80 का क्वार्टर 120 में ; पूर्व सीएम उमा ने किए 6 ट्वीट

उज्जैन (नप्र)। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उज्जैन के पास खुलेआम शराब पी रहे लोगों की भीड़ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। जीतू का कहना है कि इस शराब दुकान का बोर्ड पिपलाई गांव के नाम से लगा है, असल में ये गांव से करीब 12 किलोमीटर दूर, उज्जैन नगर सीमा समाप्त होते ही आगर रोड पर संचालित हो रही है।

जीतू ने शराब के रेट पर सवाल उठाते हुए कहा- 80 का क्वार्टर 120 में बेच रहे हैं। यानी लूट मची हुई है। दुकान पर कुछ रेट छपे हैं, लेकिन वसूली कुछ और हो रही है। जीतू पटवारी उज्जैन से राजस्थान जा रहे थे, तभी आगर रोड पर खिलचीपुर के पास अहमदनगर में लगी शराब दुकान का वीडियो बनाया। उधर, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर अपनी शराबबंदी की मुहिम से जुड़ी 6 पोस्ट की। उन्होंने कहा- क्या हम शराब वितरण नीति के प्रति लापरवाह हो गए हैं? चौकीदार अभी जिंदा है। हाथ में पत्थर की जरूरत नहीं लगती, गाय के गोबर की चोट ज्यादा भारी पड़ेगी। पटवारी ने मौके पर वीडियो बनाते हुए कहा, यहां न केवल दुकान अवैध रूप से संचालित हो रही है, बल्कि सैकड़ों लोग सड़क किनारे बैठकर खुलेआम शराब पी रहे हैं। कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है। यह शराबबंदी नहीं, बल्कि जनता के साथ धोखा है। उन्होंने दावा किया कि यहां करीब 1500 लोग एक साथ खुलेआम शराब पी रहे हैं और यह सब सरकार की मिलीभगत से हो रहा है।

धार्मिक नगरी की सीमा से शिफ्ट क्यों नहीं किया- पटवारी ने वीडियो शेयर करते हुए सवाल उठाया कि जब धार्मिक नगरी में शराबबंदी लागू है, तो फिर इसकी सीमा के ठीक बाहर शराब दुकान खोलना किस नीति का हिस्सा है? शराबबंदी सिर्फ दिखावा है।